www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 32 | गोरखपुर, 23 फरवरी 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

पीएम मोदी से मिलीं सीएम रेखा गुप्ता, विकास के रोडमैप पर की चर्चा

नई दिल्ली। दल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शीर्ष कुर्सी संभालने के बाद पहली बार शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। गुप्ता और पीएम मोदी के बीच आने वाले समय में दिल्ली के विकास पर बातचीत हुई।

नए सीएम ने अपने कार्यकाल के दूसरे दिन महिला सम्मान योजना को लेकर भी अहम बैठक बुलाई। इस-ासे पहले दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली में खोदी गई सड़कों, क्षतिग्रस्त सड़कों और यातायात से संबंधित सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए।" पहली बार विधायक बनीं गुप्ता ने गुरुवार को छह मंत्रियों के साथ रामलीला मैदान में एक भव्य समारोह में शपथ ली, जो 27 साल से अधिक के अंतराल के बाद राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा की सत्ता में वापसी का प्रतीक है। वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किए गए महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता देने के वादे पर चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी (आप) विधायकों की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ बैठक के लिए समय मांगा है।

आतिशी ने शनिवार को गुप्ता को लिखे पत्र में सवाल उठाया कि महिलाओं को वित्तीय सहायता देने की योजना को नयी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मंजूरी क्यों नहीं दी गई, जबकि प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रैली में इसका वादा किया था।

भाजपा ने इस महीने की शुरूआत में हुए विधानसभा चुनाव में 'आप' को शिकस्त दी थी, जिसके बाद गुप्ता और उनके मंत्रिपरिषद ने बीते बृहस्पतिवार को पद की शपथ ली थी।

वातावरण को अनुकूल बनाने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की: योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि 'ग्लोबल वार्मिंग' पर्यावरण प्रदूषण की चेतावनी है। शनिवार को योगी आदित्यनाथ 2,850 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रहे कुंभी, लखीमपुर में भारत के पहले 'बायो-पॉलिमर प्लांट' का शिलान्यास करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति हम लोग जितना जागरुक होंगे, पर्यावरण हमें जीने के लिए उतना ही अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएगा। योगी ने कहा, दुनिया पर्यावरण प्रदूषण के प्रति चिंतित है। खराब मौसम और 'ग्लोबल वार्मिंग' के बीच संबंध का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर प्रतिकूल वातावरण मनुष्य ने बनाया है तो वातावरण को अनुकूल बनाने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही होगी! इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिकारी और पार्टी सदस्य उपस्थित थे।

अरविंदर सिंह लवली को मिली खास जिम्मेदारी

नई दिल्ली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज भारतीय जनता पार्टी नेता अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी (सोमवार) को होगा, जहां दोपहर 2:00 बजे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इससे पहले नवनिर्वाचित विधायक सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। दिल्ली विधानसभा बुलेटिन के अनुसार, एलजी सक्सेना 25 फरवरी को विधानसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बाद में दिन में, विधानसभा एलजी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए खुली रहेगी। 26 फरवरी को सुबह 11 बजे एलजी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। बुलेटिन में कहा गया है कि अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्ताव का नोटिस सचिव, विधान सभा को शनिवार, 22 फरवरी, दोपहर से पहले तक दिया जा सकता है। भाजपा नेता रेखा गुप्ता, जिन्होंने गुरुवार को पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ने कुछ घंटों बाद अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की और दो प्रमुख निर्णयों की घोषणा की - 5 लाख रुपये के टॉप-अप के साथ आयुष्मान भारत योजना को लागू करना और विधानसभा की पहली बैठक में 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट पेश करना।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिपरिषद के विभागों की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र की प्रमुख योजना को राष्ट्रीय राजधानी में लागू करेगी। यह भाजपा का चुनाव पूर्व वादा था, जिसने योजना को लागू नहीं करने के लिए आप सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट पेश करने की भी घोषणा की, जिसे आप सरकार ने पेश नहीं किया था।

केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट : गंगा जल में घुली ऑक्सीजन के स्तर को देखते हुए वैज्ञानिक एकमत

स्नान करने योग्य है गंगा की निर्मल धारा

महाकुम्भ नगर। महाकुम्भ में एक ओर देश-दुनिया के करोड़ों भक्त रोजाना त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में स्नान करके खुद को धन्य मान रहे हैं, वहीं हाल ही में आई केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की एक रिपोर्ट ने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया था। इसी संदेह को देखते हुए देश के प्रख्यात वैज्ञानिक गंगा जल में स्नान को लेकर आई रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक तरफ उसे अपूर्ण बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट के अंशों को गलत ढंग के प्रसारित करने का संदेह जता रहे हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे तत्वों का रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है जो इसे अपूर्ण बनाती है। ऐसे में, केवल इस रिपोर्ट के आधार पर गंगा जल की गुणवत्ता पर सवाल उठाना ठीक नहीं रहेगा। वैज्ञानिकों ने संगम के जल को स्नान योग्य बताया है।

शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान स्कूल के सहायक प्रोफेसर डॉ. अमित कुमार मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह तथा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर आरके रंजन ने एकमत स्वर में कहा कि मौजूदा रिपोर्ट के आधार पर भी गंगा जल क्षारीय है, जो कि स्वस्थ जल निकाय का संकेत है। जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर इसे स्नान योग्य ही माना जाएगा।

प्रयागराज के पानी में फेकल बैक्टीरिया के संदूषण की रिपोर्ट पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान स्कूल के सहायक प्रोफेसर डॉ. अमित कुमार मिश्रा ने कहा कि हमें और अधिक डाटा सेट की आवश्यकता है। महाकुम्भ में बहुत बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। अगर आप कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की बात करें, तो यह कोई नई बात नहीं है। उनके अनुसार, अगर आप अमृत स्नान के चरम के डाटा को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उस समय ई.कोली

बैक्टीरिया चरम पर होता है। इसलिए, निष्कर्ष रूप में, मैं कहूंगा कि हमें और अधिक डाटा सेट की आवश्यकता है। हमें और अधिक मापदंडों व अधिक निगरानी स्टेशनों की आवश्यकता है, खासकर धारा के नीचे। स्नान के उद्देश्य से, 3 माइक्रोग्राम प्रति लीटर सुरक्षित है और हम कह सकते हैं कि पानी नहाने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप संगम घाट के डाटा में बदलाव देखें, तो आप पाएंगे कि यह 3 के आसपास उतार-चढ़ाव कर रहा है। कभी-कभी, यह 4, 4.5 हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि घुलित ऑक्सीजन का स्तर जो हम देखते हैं वह एक बहुत ही स्वस्थ जल निकाय का संकेत है और साथ ही अगर आप पीएच रेंज देखें, तो वे सभी क्षारीय पानी है, जो कि अच्छा माना जाएगा।

प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पानी की गुणवत्ता पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पानी में फीकल कोली-फॉर्म (बैक्टीरिया) के बढ़े हुए स्तर की बात कही गई है। मेरा मानना है कि सीपीसीबी को रिपोर्ट पर और काम करने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास पूरा डाटा नहीं है। उनके अनुसार, रिपोर्ट में नाइट्रेट और फॉस्फेट का स्तर गायब है। वहीं, रिपोर्ट में दिखाए गए अनुसार पानी में घुली ऑक्सीजन का स्तर अच्छा है। ऐसे में, मौजूदा डाटा के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि त्रिवेणी संगम का पानी नहाने के लिए उपयुक्त है।

प्रयागराज के गंगाजल में फीकल बैक्टीरिया के संदूषण की रिपोर्ट पर, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर आरके रंजन ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डाटा में काफी अंतर है। यह निष्कर्ष निकालना कि पानी नहाने के लिए असुरक्षित है, दरअसल जल्दबाजी होगी। प्रयागराज के पानी में नहाने के लिए सुरक्षित नहीं है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त डाटा नहीं है। ऐसा ही दावा गढ़मुक्तेश्वर, गाजीपुर, बक्सर और पटना को लेकर भी किया गया है। उनके अनुसार, ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि बड़ी संख्या में लोग एक ही पानी में नहाते हैं। यह भी मायने रखता है कि जल का नमूना कहां से और कब लिया गया है।

रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात

विकास यात्रा में आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहेगा

नई दिल्ली। दल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पदभार संभालने के एक दिन बाद शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में और उपराष्ट्रपति धनखड़ से राष्ट्रीय राजधानी में उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में मुलाकात की। इससे पहले दिन में, रेखा गुप्ता ने समर्थकों से मुलाकात के दौरान आभार व्यक्त किया और कहा कि दिल्ली सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी, जिसे आप ने 'अवरुद्ध' कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे के मुद्दों के बारे में भी बात की जिन पर आगामी कैबिनेट बैठकों में चर्चा की जाएगी।

मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के नए सीएम ने कहा कि कल कैबिनेट बैठक में हमने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी, जिसे आप ने रोक दिया था। योजना जल्द ही सार्वजनिक डोमेन में होगी। आज, हमने कैबिनेट के साथ बैठक के लिए पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है। हम गड्ढों के मुद्दे को उठाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने भी लोगों से बातचीत की, क्योंकि शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग शालीमार बाग में उनके आवास के बाहर उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुए थे। लोग मालाएं और फूलों के गुलदस्ते लेकर उन्हें बधाई देने पहुंचे। रेखा गुप्ता ने गुरुवार को रामलीला मैदान में एक भव्य समारोह में दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली में भाजपा की दूसरी और राष्ट्रीय राजधानी में चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिपरिषद को पद की शपथ दिलाई। छह अन्य मंत्रियों प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने भी पद की शपथ ली। शालीमार बाग सीट से निर्वाचित रेखा गुप्ता ने दिल्ली में भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव और इसकी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है।

राजदूतों ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपे परिचय पत्र

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गत बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में सूडान और फलस्तीन सहित पांच देशों के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए।

राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि जिन लोगों ने अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए, उनमें पनामा गणराज्य के राजदूत अलोंसो कोरेया मिगुएल, गुयाना के उच्चायुक्त धर्मकुमार सीराज और सूडान गणराज्य के राजदूत मोहम्मद अब्दुल्ला अली अलतोम शामिल हैं।

बयान में कहा गया है कि डेनमार्क के राजदूत रासमस अबिल्डगार्ड क्रिस्टेंसन और फलस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला मोहम्मद ए अबु शावेश ने भी राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए।

महाशिवरात्रि के लिए बढ़ाई गई आपातकालीन चिकित्सा सुविधा

महाकुम्भ नगर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महाकुम्भ में संगम स्नान के लिए आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अभूतपूर्व रूप से सशक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देश पर स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल, प्रयागराज में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है। साथ ही आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाकर 147 कर दी गई है, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य के लिहाज से किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉ. संतोष सिंह के अनुसार वर्ष 2017 में केवल 52 आईसीयू बेड वाले एसआरएन अस्पताल में अब आ-ईसीयू बेड बढ़ाकर 147 कर दिए गए हैं। महाकुम्भ के दौरान किसी भी आपात चिकित्सा स्थिति से निपटने के लिए यह काफी कारगर साबित होगा।

जेपी नड्डा, सीएम योगी संग महाकुंभ में लगाई पवित्र डुबकी

महाकुंभ नगर । केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाकुंभ में पहुंचे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। इससे पहले सीएम आदित्यनाथ ने महाकुंभ नगर में केंद्रीय मंत्री नड्डा का जोरदार स्वागत किया। इन दोनों प्रमुख नेताओं की त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना महाकुंभ में मौजूद श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लेटे हनुमानजी मंदिर में पूजा-अर्चना की।

नड्डा ने संगम तट पर परिवार के साथ पूजा-अर्चना भी की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आयोजन 144 साल बाद हो रहा है। यह हिंदू धर्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रमों में से एक है। इस खास मौके पर लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं, जिसे धार्मिक प्रगति और पापों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनकी कुल संख्या 600 मिलियन से अधिक है।

महाकुंभ मेला प्रशासन के मुताबिक, प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ से ज्यादा हो गई है। शनिवार को दोपहर तक 71.18 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर चुके थे। महाकुंभ का आखिरी स्नान 26 फरवरी को महा शिवरात्रि पर होने वाला है। अब तक स्नान करने वाले कुल श्रद्धालुओं की संख्या का विश्लेषण करें तो मौनी अमावस्या के दौरान सबसे अधिक संख्या, लगभग 8 करोड़, ने स्नान किया। मकर संक्रांति पर साढ़े तीन करोड़ श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया. 1 फरवरी और 30 जनवरी को 20 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया और पौष पूर्णिमा पर 17 मिलियन श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। इसके अलावा, बसंत पंचमी पर 25.7 मिलियन श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जबकि माघी पूर्णिमा पर 20 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया।

27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में आयी भाजपा ने रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री दे दिया। इसके पहले भाजपा की सुषमा स्वराज, कांग्रेस की शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी की आतिशी मलिना दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं।

दिल्ली में डबल इंजन की सरकार

आखिरकार दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन सरकार बन गई। चुनाव परिणाम आने के बाद तमाम उहापोह के बाद भाजपा ने दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री दिया। इस रूप में भाजपा ने रेखा गुप्ता का चयन किया जिसके शपथ ग्रहण में राजग के कुनबे को भी एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को हराकर आए प्रवेश वर्मा को बहत उम्मीदें थी कि वे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे उनके पिता साहब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे और केजरीवाल को हराने के लिए प्रवेश वर्मा ही नहीं कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र भी उसी सीट से चुनाव मैदान में थे। लेकिन लाटरी रेखा गुप्ता की निकली। इस प्रकार 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में आयी भाजपा ने रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री दे दिया। इसके पहले भाजपा की सुषमा स्वराज, कांग्रेस की शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी की आतिशी मलिना दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। भाजपा ने चुनाव के दौरान किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा विवादों की वजह से नहीं दिया था, जिसकी वजह से जितने भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे वे वैसे ही अपने का समझ रहे थे जैसी की एक बुनकर को लेकर कहावत है 'जिसकी कमर में धागा वही से मनवा लागा।' यानी सभी दावेदार अपने को मुख्यमंत्री ही समझ रहे थे। प्रवेश वर्मा को अपनी विरासत की वजह से उम्मीदें कुछ ज्यादा ही थीं लेकिन रेखा गुप्ता का संघ का नाता सभी दावेदारों पर भारी पड़ गया।

अब डबल इंजन की सरकार होने से एक ही राजनीतिक दल को हित सधेगा तो न तो उपराज्यपाल को कोई समस्या दिखेगी और न ही केन्द्र सरकार को ही किसी प्रकार का अडंगा लगाने को अवसर मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की सरकार की अपनी कोई अलग हैसियत ही नहीं रहेगी। अब देखना होगा कि जिन वादों को करके दिल्ली में भाजपा सरकार 27 साल बाद आई है उसका पहला सामना तो यमुना नदी की साफ-सफाई से होने जा रहा है जो उसका पहला एजेण्डा है।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की ही डबल इंजन सरकार है इसलिए अब दिल्ली को पानी के संकट से शायद न जूझना पड़ा। अभी तो दिल्ली में भाजपा की नई जीत का स्वाद वहां की जनता चखेगी और उन वादों को परखने का काम करेगी जिसे पूरा करने का दायित्व दिल्ली की सरकार पर होगा। बिजली, पानी साफ-सफाई और सोशल वेलफेयर तक ही यह सरकार सीमित रहेगी क्योंकि न तो उस कानून व्यवस्था देखना है और. न ही अन्य राज्यों की भांति अन्य दायित्व ही उसके पास है। यह तो कुल मिलाकर आधा अधूरा राज्य है चूंकि केन्द्र की नाक के नीचे हैं इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है।जिसे भाजपा आप को तब तक बर्दाश्त कर रही थी जब तक आम आदमी पार्टी ने गुजरात विजय का सपना नहीं देखा था। गुजरात और गोवा में चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ा। चूंकि भाजपा केन्द्र में कांग्रेस को हटाकर आई थी, जिसमें अन्ना हजारे केजरीवाल और उनके साथियों का भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा किये गए। आंदोलन की बड़ी भूमिका थी, जिसके पीछे भाजपा और संघ की राजनीति और रणनीति खड़ी थी। यही कारण है कि आप को लेकर भाजपा को कोई खास परेशानी तब तक नहीं थी जब तक उसने गुजरात के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किया था। गुजरात में उसे कोई सफलता नहीं मिली लेकिन वह राष्ट्रीय पार्टी जरूर बन गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप को वहीं-वहीं सफलता मिली जहां कांग्रेस की सरकार थी यही कारण है कि केजरीवाल की पार्टी को भाजपा की बी टीम का तमगा दिया जाता रहा है। दिल्ली की डबल इंजन की सरकार के लिए यदि वह कुछ करना चाहती है तो कोई संकट इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके सामने उस प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है जो आप की सरकार के समय आती थी। भाजपा का तो यह कहना है कि वह पांच साल के लिए नहीं पन्द्रह साल के लिए आई है तो अब तो आप से ज्यादा कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि वह कौन सा सपना देख रही है। आप को हराकर वह खुद भी हारकर बहुत खुश है लेकिन तीसरी बार विधानसभा में शून्य रहकर वह कौन सी रणनीति अपनायेगी या फिर वह बिल्ली के भाग्य से छीका टूटने का इंतजार करेंगी जो फिलहाल इस पांच साल में तो नहीं होने वाला है। इसका अहसास तो कांग्रेस को हो ही गया है, जो इस इन्तजार में प्रायः रहती है कि जब भाजपा से लोग नाराज होंगे तो कांग्रेस को सत्ता सौंप देंगे।

रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ ही समीकरण बैठाने के लिए प्रवेश शर्मा सहित 6लोगों को मंत्री परिषद क शपथ दिलाई गई है इस ट्रेन के माध्यम से सामाजिक जातीय समीकरण को भी साधा गया है।

दिल्ली में भी डबल इंजन के सरकार होने से दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अब काम ही नहीं रह गया होगा क्योंकि जब तक केन्द्र और राज्य में दूसरी पार्टियों की सरकार रहती है तब तक प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल के पास काम अधिक रहता है क्योंकि के राजनीतिक हितों की पूर्ति करनी होती है। यही कारण है कि विभिन्न मसलों को लेकर केजरीवाल सरकार को बार-बार दिल्ली की सरकार को सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ता था। वह चाहे बाबुओं की नियुक्ति का और तैनाती का मामला हो या अन्य नियम अधिकार का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही निर्वाचित सरकार के अधिकारों का संरक्षण दिया केन्द्र सरकार ने रातों-रात कानून बनाकर दिल्ली राज्यपाल को मजबूती दे दी जिससे दिल्ली की सरकार कोई काम काज कर ही न सके। उसके माई बाप उपराज्यपाल ही बने रहे।

अपनी इति कथा लिख रहा इंडिया ब्लाक

दिल्ली के चुनाव परिणाम आने से पहले ही सवाल उठ चला था कि क्या 'इंडिया' ब्लॉक खुद अपनी इतिकथा लिख रहा है ? इस सियासी गठबंधन के पुराने कमिसार और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मतदान-पूर्व मांग बुलंद की थी कि

दिल्ली चुनाव के बाद ब्लॉक के सभी सहयोगी एक साथ जुटें और फैसला करें कि आगे उन्हें साथ कैसे चलना है? वह दिल्ली में आप और कांग्रेस के आमने-सामने हो जाने से आहत थे। उनकी आशंकाएं सच साबित हुई। अब इस ब्लॉक का अगला इम्तिहान बिहार में होना है। वहां अक्तूबर-नवंबर में चुनाव हैं।

बताने की जरूरत नहीं कि तेजस्वी यादव की अगुवाई, वाला राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दशकों से साथ चुनाव लड़ते आए हैं। इसके बावजूद इस सबल क्षेत्रीय दल के कर्ताधर्ता अक्सर ठंडी सांस भरकर कहते हैं, काश ! 2020 के विधानसभा मतदान से पूर्व हमने कांग्रेस को इतनी सीटें न दी होतीं! उस चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त मोलभाव के जरिये 70 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारने में कामयाबी हासिल करली थी। इनमें से मात्र 19 पर जीत हासिल हो सकी। अंतिम नतीजों के अनुसार, तेजस्वी यादव महज 13 हजार वोट और 12 सीट से पीछे रह गए थे। अगर राजद और वामदलों के कंधे पर संवार कांग्रेस अपने इन सहयोगियों के समान परिणाम देती, तो ऐसा न होता। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी के पुरोधा भी यही रंज जताते पाए जाते थे। इससे एक वर्ष पूर्व तमिलनाडु में यही दुखांत दोहराया गया था! नतीजतन, द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने वर्ष 2021 में हुए अगले विधान सभा चुनाव में कांग्रेस की लगभग 40 फीसदी सीटें काट लीं। क्या अब बिहार में तेजस्वी यादव इसी सूत्र पर काम करेंगे? यदि ऐसा होता है, तो यह कांग्रेस के लिए बुरी खबर होगी। एक के बाद एक राज्य गवाती कांग्रेस को हिमाचल तेलंगाना और कर्नाटक के अलावा सिर्फ अपने सहयोगियों का सहारा शेष रह गया है। झारखंड और तमिलनाडु इसका सबल उदाहरण है।

वजह? शिवसेना के पुराने काडर को कांग्रेस का साथ मंजूर नहीं था। उद्धव समय रहते इस विक्षोभ को सम्हाल न सके और उनकी जबरदस्त बगावत हुई।

बागी नेता एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तोहफे में दी। इस राजनीतिक कवायद के कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस को अधिक

विधायक विधायक बल के बावजूद उप-मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। उनकी पार्टी ने इस कर्तव्य-भाव को याद रखा। हालिया विधानसभा चुनावों के बाद शिंदे मुंह फुलाते रह गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एकबार फिर देवेंद्र फडणवीस को सत्ता की कमान सौंप दी। शिंदे अब उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं।

कांग्रेस के लिए यह चुनाव बड़ा अवसर था। लेकिन उसने मत महाराष्ट्र चुनाव में न केवल उद्धव को

मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया, बल्कि अधिक सीट हथियाने के लिए बखेडे किए। इससे मतदाता के समक्ष गठबंधन को साख और पवार-ठाकरे जोड़ी के प्रति सहानुभूति समाप्त हो गई। यह उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ अन्याय था। कोई भरोसा नहीं कि आगामी दिनों में महाराष्ट्र से अलगाव की खबरें सुनाई पड़ने लगी हैं।

अरविंद केजरीवाल भी चाहते थे कि -गुजरात के चुनाव में कांग्रेस उनका साथ दे। उन्होंने लंबे समय तक माकूल जवाब का इंतजार किया, पर जवाब अधर में ही लटका रहा। नतीजा सामने है। आम आदमी पार्टी ने 13 फीसदी के करीब मत हासिल किए, जो सीधे तौर पर कांग्रेस की झोली से सरके थे। तय है, आप का वजूद कांग्रेस की कीमत पर खड़ा हुआ था। इंडिया ब्लॉक बनने के बाद आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि बदले हालात में हरियाणा विधानसभा चुनाव में उसे समुचित महत्व हासिल होगा, लेकिन यहां भी गुजरात-गाथा दोहराई गई। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने बिना कांग्रेस से दरयाफ्त किए दिल्ली में अपने उम्मीदवार उतार दिए। इस बार कांग्रेस ने वही भूमिका अदा की, जो कभी केजरीवाल ने हरियाणा और गुजरात में निभाई थी। आप मात्र दो प्रतिशत मतों से भाजपा से पीछे रह गई, जबकि कांग्रेस ने अपने मत प्रतिशत में दो फीसदी के करीब का इजाफा किया। यह दो फीसदी मत यदि कांग्रेस- आप के गठबंधन को मिले होते, तो आज न केवल दिल्ली की कहानी कुछ और होती, बल्कि इंडिया ब्लॉक को भी मजबूती मिलती।

सवाल उठता है, कांग्रेस अपने अतीतजीवी अभियान को सियासी संगी-साथियों की कीमत पर कब तक सहलाती रहेगी ? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अपनी क्षेत्रीय इकाइयों पर केंद्रीय नेतृत्व की समुचित पकड़ नहीं है। चर्चा है कि राहुल गांधी हरियाणा और गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे। वह दिल्ली में भी समझौते के पक्षधर थे, परंतु वहां की प्रांतीय इकाइयों को लगता था कि कांग्रेस अपने बूते पर बेहतर करेगी। चुके हुए जनाधार और थके हौसलों वाले उसके परिवारवादी क्षत्रप तर्क भले लच्छेदार दें लेकिन उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। यही नहीं, कांग्रेस अब जिस तरीके से जातीय जनगणना के बहाने

पिछड़े वर्ग को आंदोलित करना चाह रही है, उससे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और एम के स्टालिन जैसे सहयोगियों के भी कान खड़े हो सकते हैं। आखिर इसी वोट बैंक पर तो वे अब तक अपनी सियासत की इमारत खड़ी करते आए हैं।

कांग्रेस आजाद भारत में अब तक के सबलतम प्रतिद्वंद्वी मोदी और शाह से मुकाबिल है। हर हार के बाद उसके चाहने वाले पूछते हैं कि वह कब सुधरेगी, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तो शायद कांग्रेस के कर्णधारों के पास भी नहीं है।

तय है, देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने बलबूते चुनाव जीतने की ताकत गंवाती जा रही है।

कांग्रेस के दोस्तों को यह सुनकर बुरा लग सकता है, पर उन्हें अपने चिर प्रतिद्वंद्वी भाजपा से सबक लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में बरसों तक अपने दोयम दर्जे से गिला किए बिना चुनाव-दर-चुनाव मनचाहीं मंजिल हासिल की है। खुद बिहार इसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के पास अधिक बिधायक होने के बावजूद बरसों से उसने नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता मान रखा है। यहां याद दिलाना जरूरी है कि इन्हीं नीतीश कुमार को कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव से पूर्व इंडिया ब्लॉक का संयोजक नहीं बनने दिया था। एक बार फिर भाजपा के पाले में जा खड़े हुए थे। इससे नुकसान किसका हुआ ? सिर्फ कांग्रेस और इंडिया का। महाराष्ट्र का मामला भी कुछ ऐसा ही है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुराने साथियों में एक थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी से अधिक सीटें हासिल की थीं। जाहिर है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का हक था, जबकि उद्धव ठाकरे का मानना था कि भाजपा को यह सफलता शिवसेना के लंबे साथ की वजह से मिली है। वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना अधिकार जता रहे थे। बदले हालात में भगवा दल को यह स्वीकार्य नहीं था। आगे क्या हुआ, सब जानते हैं। उद्धव चिर-प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार गठित करने में कामयाब तो रहे, पर एवज में अपनी पार्टी और प्रतिष्ठा गंवा बैठे।

धूमधाम से मना सरदार भगवान सिंह विवि का पहला दीक्षांत समारोह

सिर्फ नौकरी की तलाश में ना रहकर रचनात्मक सोच से स्टार्टअप शुरू करें विद्यार्थी : राज्यपाल

देहरादून । विद्यार्थी केवल नौकरी की तलाश तक सीमित ना रहें, बल्कि वह कौशल, रचनात्मक सोच और कठोर परिश्रम के बल पर स्टार्टअप शुरू करें और सफल उद्यमी बनें। आज के समय में युवा पीढ़ी के लिए असीम संभावनाएं हैं और यदि वे आत्मनिर्भरता और नवाचार को अपनाएं तो ना केवल अपने लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। ऐसा विचार राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने बालावाला स्थित सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित पहले दीक्षांत समारोह के दौरान व्यक्त किया।

गत दिनों शुक्रवार को दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों में 944 छात्र-छात्राओं को डिग्री दी गई। इसके साथ ही 77 स्वर्ण और 34 रजत पदक दिया गया। राज्यपाल ने छात्र-छात्राओं को उपाधि देते हुए कहा

कि वह ऐसे समय में एक नई यात्रा की शुरूआत कर रहे हैं, जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। कहा कि देश की प्रगति में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज का युग क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का है। भारत इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में अनुकूलनशीलता, नैतिक नेतृत्व और निरंतर कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया। विवि के कुलपति प्रो. डॉ. जे कुमार ने विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके साथ ही विवि के अध्यक्ष डॉ. गौरव दीप सिंह ने कहा कि यह दीक्षांत समारोह ना केवल वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम हैं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरूआत का प्रतीक है।

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट: बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में एक भी स्टार्टअप नहीं

देहरादून । पर्वतीय जिलों में बागेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में एक भी स्टार्टअप नहीं है। यह खुलासा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से हुआ है। अर्थ एवं संख्या विभाग के राज्य में चल रहे स्टार्ट पर कराए गए एक सर्वे के मुताबिक, राज्य के पर्वतीय जिलों में कुल सर्वेक्षित स्टार्टअप का 15 फीसदी है। जबकि, 85 फीसदी स्टार्टअप मैदानी जिलों में हैं।

केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें बेशक राज्य के शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, लेकिन पहाड़ में इसकी तस्वीर बहुत सुहावनी नहीं है। अलबत्ता मैदानी जिलों में स्टार्ट अप को लेकर खासतौर पर पुरुषों और युवाओं ने ज्यादा उत्साह दिखाया। सबसे अधिक 62 प्रतिशत सक्रिय स्टार्टअप देहरादून जिले में काम कर रहे हैं।

वर्ष 2023-24 में राज्य में पंजीकृत 152 स्टार्टअप का सर्वे में यह खुलासा हुआ कि 21 स्टार्टअप सहयोग न मिल पाने के कारण बंद पड़े थे जबकि 30 स्टार्ट अप निष्क्रिय मिले। इनमें से 53 प्रतिशत वित्तीय समस्याओं, 23 प्रतिशत सरकार का सहयोग न मिलने, 21 प्रतिशत निवेशकों की कमी और अनुपयुक्त क्षेत्र में काम करने से बंद हो गए। इनमें से क्रियाशील 101 स्टार्ट अप पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, साझेदारी फर्म, सीमित देनदारी फर्म व अन्य रूप में संचालित हैं। सबसे अधिक 40

फीसदी सक्रिय स्टार्ट अप में एक लाख से 10 लाख तक की प्रारंभिक पूंजी निवेश हुआ। एक लाख से कम पूंजी निवेश वाले 30 प्रतिशत ,31 प्रतिशत 10 लाख उससे अधिक पूंजी वाले हैं। विनिर्माण पर आधारित स्टार्ट सबसे अधिक सकल मूल्य वृद्धि वाले हैं।

कुल संचालित 101 स्टार्टअप में पुरुषों का दबदबा है। 76 प्रतिशत स्टार्ट के संस्थापक पुरुष हैं, जबकि 24 प्रतिशत के महिला। 30 वर्ष से कम आयु के संस्थापकों में 27 प्रतिशत पुरुष व सात प्रतिशत महिलाएं, जबकि सर्वाधिक 14 प्रतिशत महिलाएं 30 से 45 आयु वर्ग की संस्थापक हैं। इसी आयु वर्ग 36 प्रतिशत पुरुष संस्थापक मिले।

सर्वे में स्टार्टअप स्वामियों, साझेदारों और संचालकों ने नीति को और अधिक व्यावहारिक बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ाने पर बल दिया और नए विचारों को बाजार और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए उद्योग विभाग के तहत एक कॉर्पस फंड बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने इन्क्यूबेशन सेंटर व स्टार्टअप स्वामियों के मध्य परस्पर समन्वय को मजबूत करने के लिए औद्योगिक इकाइयों के साथ समय-समय पर औद्योगिक मीट कराने पर जोर दिया।

सर्वे के मुताबिक, प्रदेश में सबसे अधिक 14-14 प्रतिशत कृषि व विनिर्माण से जुड़े हैं। 11 प्रतिशत आ-ईटी परामर्श व समाधान से, आठ-आठ प्रतिशत शिक्षा व टूरिज्म से, सात प्रतिशत खाद्य से छह प्रतिशत स्वास्थ्य व जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं। इनके अलावा उद्यम एवं सामाजिक उद्यम, परिवहन व रसद, दो-दो प्रतिशत मीडिया और मनोरंजन, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा व नवीनीकरण ऊर्जा से जुड़े हैं।

आत्मघाती गोल से कांग्रेस को बचना होगा

भारत के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ा आत्मघाती गोल - 2024 के लोकसभा चुनाव के दौर में कांग्रेस ने किया था जब कि उसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनने दिया था। यह नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने पूरे देश का दौरा कर गैर भाजपाई मुख्यमंत्री तथा विरोधी राजनीतिक दलों के प्रमुख से बात की थी तथा भाजपा विरोधी गठबंधन की नींव डाली थी। नीतीश कुमार ही सच्चे अर्थों में इंडिया गठबंधन के शिल्पी थे और उनके संयोजक बनने पर किसी दल को कोई आपत्ति नहीं थी पर कांग्रेस ने अतिमहत्वाकांक्षा के चलते नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनने दिया जिसके फलस्वरूप नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो गए तथा राजग में शामिल हो गये । यदि नीतीश कुमार संयोजक के रूप में इंडिया गठबंधन में रहते तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार में इंडिया गंठबंधन की सीटों में कम से कम तीस की वृद्धि होती इसका असर अन्य प्रांतों पर पड़ता और इंडिया गठबंधन को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिलता । कांग्रेस के आत्म घाती गोल के कारण ही केन्द्र में इंडिया गठबंधन की सरकार न बन सकी। यदि केन्द्र में इंडिया गठबंधन को सरकार होती तो भाजपा महाराष्ट्र में वह खेला न कर पाती जो उसने किया। खेल के मैदान में हॉकी या फुटबॉल खेलने वाली टीमों में जीतने वाली टीम का कोई खिलाड़ी आत्मघाती गोल कर देता है और टीमवराजित हो जाती है। आत्मघाती गोल का अर्थ है-कि- जो गोल प्रतिद्वन्दी टीम को करना चाहिए जीतने वाली टीम किसी-चूक से कर देती है। इसी प्रकार राजनीति के मैदान में भी कभी-कभी किसी पार्टी का कोई नेता आत्मघाती गोल कर देता है और उसकी पार्टी-चुनाव जीतते-जाते हार जाती है जिस पार्टी में अनुशासन को कमी होती है जिसका केन्द्रीय नेतृत्व कमजोर होताहै, वह अक्सर आत्मघाती गोल का शिकार हो जाती है। दूसरा आत्मघाती गोल कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में किया 12024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में मिले समर्थन से कांग्रेस को यह मुगालता हो गया कि विधानसभा चुनाव में उसकी जीत सुनिश्चित है। इसीलिए न तो अपने आम आदमी पार्टी और न ही समाजवादी पार्टी के लिए सीट छोड़ी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने तो हरियाणा में कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। पर आम आदमी पार्टी ने पचासों उम्मीदवार खड़े किये। अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा विरोधी वोटों के बंटवारे के कारण ही कांग्रेस उम्मीदवार पराजित हो गए। आम आदमी पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई पर वोट का बंटवारा कर कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक दिया। आधे दर्जन से अधिक सीटों पर कांग्रेस व आम आदमी पार्टी को मिलाकर भाजपा से अधिक वोट मिले। कांग्रेस का अहंकार व अति आत्मविश्वास उसे हरियाणा में ले डूबा। दिल्ली में भी कांग्रेस ने वोटकटवा भूमिका निभाकर आम अदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने की भूमिका बखूबी निभायी। आम आदमी पार्टी को 43.7 प्रतिशत वोट मिले जबकि भाजपा को 45.56 प्रतिशत लोकप्रिय वोट मिले। कांग्रेस पार्टी को 6.34 प्रतिशत मत मिले। चूंकि भाजपा व कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी के विरूद्ध एक ही प्रकार का नैरैटिव चला रहे थे, इसलिए आप के लोकप्रिय मतों में 2020 के चुनाव की अपेक्षा जो गिरावट आई उसका लाभ भी कुछ न कुछ कांग्रेस को मिला। दिल्ली की 14 सीटों पर यदि कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के वोट मिला दिए जायें तो भाजपा के जीते उम्मीदवार से अधिक मत हैं। इस प्रकार कांग्रेस ने हरियाणा का बदला आम आदमी पार्टी से दिल्ली में लिया। इसे कांग्रेस के नेता खुलकर कहते भी हैं।

घूँघट की बगावत

23 फरवरी 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

मोदी-ट्रंप की मुलाकात से कितना लाभ होगा

अमेरिकी उथल-पुथल के बीच वाशिंगटन में कदम रखने वाले मोदी चौथे विदेशी नेता हैं। पिछले हफ्ते इजरायली प्रधानमंत्री के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका द्वारा गाजा पट्टी पर नियंत्रण करने संबंधी अप्रत्याशित प्रस्ताव देकर तमाम विश्लेषकों को हालांकि, पिछले शुक्र- वार को जापान के प्रधानमंत्री - शिंजो इशिता के साथ ट्रंप की बैठक ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोर सकी क्योंकि इसमें मित्रता बढ़ाने की ज्यादा और टकराव की कम कमजोरी हुई थी। मोदी के साथ भी ऐसे ही व्यवहार का अनुमान है।

ट्रंप अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के निष्कासन और भारत द्वारा लिए जाने वाले अधिक सीमा शुल्क जैसे मुद्दों पर जोर दे सकते हैं। मोदी इन मुद्दों की तपिश झेलने को तैयार दिखते हैं। पिछले हफ्ते ही भारत में एलान किया है कि वह मोटर साइकिल पर आयात शुल्क कम कर रहा है।

यह एक ऐसा कदम है, जो अमेरिका के लिए भारत में हार्ले डेविडसन बाइक के अधिक निर्यात का द्वार खोल देगा। भारत अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने के लिए अमेरिका से अधिक तेल और गैस खरीदने की पेशकश भी कर सकता है। भारत से सौ से अधिक अवैध अप्र- वासी भारतीयों की वापसी को स्वीकारा हालांकि विपक्षी दलों ने वतन वापस लौट रहे लोगों के साथ किए गए व्यवहार पर नाराजगी जताई है। पर भारत ने अन्य अवैध प्रवासी भारतीयों को भी वापस लेने का इरादा जताया है। हालांकि भारत ने व्यापार पर जो कदम उठाए हैं उससे ट्रंप की भारतीय बाजार तक पहुंचने की इच्छा फिलहाल पूरी होती नहीं दिख रही है। वैसे, ट्रंप स्टील एवं पहुँचने में विफल रहे थे। यहां तक कि ट्रंप ने गोदी को दोबारा चुनाव जीतने से कुछ समय पहले 2019 में भारत को दी गई 'जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंसेस (सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली - जो एसवी) भी वापस ले ली थी। इसके तहत व्यापार में भारतको विशेषाधिकार प्राप्त था। अगर कारोबारी तनाव के बावजूद दोनो देशों के कूटनीतिक संबंध काफी हद तक पटरी पर रहे। इस स्तर ट्रंप की भारत से अधिक अपेक्षाएं होगी। लेकिन बड़ा खतरा यहकि यदि व्यापार वार्ता विफल रही तो द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो सकता है। क्योंकि ट्रंप की राष्ट्रपति पद पर दोबारा वापसी से उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। और अपने हितों से समझौते को लेकर बह अनिच्छुक दिखते हैं। ट्रंप भी यही चाहेंगे कि- भारत अमेरिकी रक्षा उपकरणों को खरीदने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करे। फरवरी-2020 की अपनी सफल भारत यात्रा को दौरान उन्होंने तीन अरब डॉलर का रक्षा रक्षा समझौता किया था। अब दोनो पक लड़ाकू वाहनों व जेट विमानों की भारतीय खरीद और साझा उत्पादन पर बात कर रहे हैं। टीम ट्रंप स्पष्ट रूप से भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता दे रही है और वह मानती है कि - वैश्विक ताकत के रूप में भारत के उभरने से हिंद प्रशांत क्षेत्र और दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। यही कारण है कि रुबियों की पहली बैठक भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया (क्वाड) के विदेश मंत्रियों के साथ हुई। ट्रेस ने यह भी संकेत दिया कि वह इस साल नई दिल्ली में क्वाड शासनाध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लेंगे। जो इसलिए खास होगा, क्योंकि यह पहला मौका होगा, जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालने के एक वर्ष के भीतर भारत का दौरा करेगा। चर्चा का दूसरा विषय तकनीकी सहयोग हो सकता है।

बाइडन सरकार ने साल 2003 में भारत के साथ 'द इनीशिएटिव ऑन क्रिटिकल ऐंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (आईसीईटी) डायलॉग' शुरू करके महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग बढ़ाने की अहम शुरूआत की थी। जून, 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए थे, तब दोनों देशों ने मिलकर जेट इंजन बनाने की घोषणा की थी, जो आईसीईटी के अंतर्गत एक ऐतिहासिक समझौता था। बाद में दोनों देशों ने जैव प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर में पहल करने, 6जी तकनीक पर विचार-विमर्श करने और क्वांटम तकनीक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। राष्ट्रपति ट्रंप भी भारत के साथ तकनीकी सहयोग पर बात कर सकते हैं, हालांकि, इसे अलग तरह से पेश किया जा सकता है। आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए प्रौद्योगिकी में सहायता और चीन के साथ प्रौद्योगिकी की दौड़ में उसे प्रभावी रूप से टक्कर देने में एक-दूसरे की मदद करना अमेरिका और भारत के लिए खासा फायदेमंद होगा।

साफ है, मोदी ने अभी वाशिंगटन जाने का सही वक्त चुना है। राष्ट्रपति ट्रंप दोस्त और दुश्मन, सभी देशों पर टैरिफ लगाने को लेकर गंभीर हैं और भारत इससे बच नहीं सकेगा। ऐसे में, बेहतर यही होगा कि भारत अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने के लिए कदम उठाने का संकेत दे और ट्रंप को आपसी संबंधों के भू-राजनीतिक महत्व की याद दिलाए। वाशिंगटन और नई दिल्ली को कारोबार के लिए एक नई पहल करनी होगी, ताकि व्यापारिक टकराव कूटनीतिक संबंधों पर भारी न पड़े, क्योंकि यह दोस्ती शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद-प्रशांत के लिए काफी अहम है।

महाकुंभ 2025 : परम्परा, अनुष्ठान और महत्ता विषयक दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी

गोरखपुर। सिद्धपीठ श्रीहनुमन्निवास धाम अयोध्या के महंत आचार्य मिथिलेशनंदिनी शनिवार को महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़ के कला संकाय के तत्वावधान में महाकुंभ 2025 : परम्परा, अनुष्ठान और महत्ता विषयक दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि दुनिया के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को व्यवस्था की दृष्टि से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस सुचारुता से सुनिश्चित किया वह अभिनंदनीय है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास धर्मनिष्ठा से संपन्न योगी आदित्यनाथ जैसा नायक है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 कई आयामों में अपूर्व है। अतीत के कुंभ आयोजनों को देखें तो इस महाकुंभ में श्रद्धा का ज्वार अपूर्व है। पहले की सरकारों ने केंद्रीय कार्यक्रम मानकर कभी कुंभ को पुरस्कृत नहीं किया लेकिन यह ऐसा पहला कुंभ है जिसमें मुख्यमंत्री ने चप्पे-चप्पे पर जाकर व्यवस्था की सुचारुता सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री के समर्पित प्रयास के चलते ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के रूप में इस धरती का सबसे बड़ा धार्मिक मेला आयोजित हुआ। संगोष्ठी में आए अतिथियों का स्वागत करते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़ के प्राचार्य डॉ. प्रदीप कुमार राव ने कहा कि यह संगोष्ठी वैचारिक महाकुंभ है। यह एक ऐसा आयोजन है जिसमें ऐसे लोग भी कुंभ की भावना से ओतप्रोत होकर नहा लेंगे जो किंचित कारणों से प्रयागराज महाकुंभ नहीं जा सके हैं। प्रयागराज महाकुंभ पर दुनिया अध्ययन कर रही है। कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है। अनपढ़, पढ़े लिखे मूर्ख, विद्वान, वैज्ञानिक, आलोचक, पक्ष, निष्पक्ष सभी अपने-अपने तरीके से इसका अध्ययन और विमर्श कर रहे हैं। डॉ. राव ने कहा कि हमारे जीवन में रोज महाकुंभ का मंथन चलता है और इस मंथन में विष और अमृत दोनों निकलता है। हमारी सनातन परंपरा अहर्निश हमें यह प्रेरणा देती है कि मंथन से निकलने वाले गरल का पान हम स्वयं करें और इससे निकलने वाले अमृत को संस्था, समाज, राष्ट्र और मानवता के हित में देते रहें। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 जितना अपनी दिव्यता, भव्यता एवं सुव्यवस्था के लिए याद किया जाएगा, उतना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रुंधे गले और उनके आंसुओं के कारण भी याद किया जाएगा। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर क्षण भर के लिए घटित अनहोनी रूपी विष को पीते हुए जब सन्यासी योगी के आंसुओं की दुनिया साक्षी बनी। सबने उनकी संवेदना को सराहा।

वर्जित विषयों पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून की आवश्यकता

हाल ही में यूट्यूब के एक कथित कॉमेडी शो से उठे राष्ट्रव्यापी विवाद के बाद आरोपी यूट्यूबर को गिरफ्तारी से राहत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियों की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में आरोपी से कहा कि उसने अपने दिमाग में भरी गंदगी को उगला है। अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया के बयान पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसकी बातों से बेटियों, बहनों और माता-पिता को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने की योजना बताएं। अन्यथा इस मामले में कोर्ट देखेगा।

उल्लेख्य है कि यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना के एक शो 'इंडियाज गॉट टेलेंट' के एक एपिसोड को

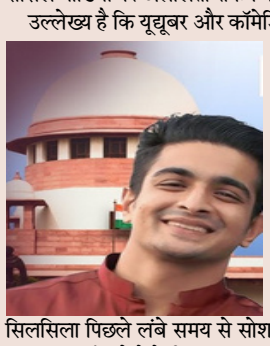

लेकर पिछले दिनों खासा विवाद हुआ। जिसको लेकर पूरे देश में तल्ख प्रतिक्रिया सामने आई । कई राज्यों में अश्लील टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। दरअसल, रणवीर ने एक प्रतिभागी से उसके माता-पिता के निजी संबंधों को लेकर आपत्तिजनक सवाल किए थे। इस अमर्यादित व अश्लील टिप्पणी को लेकर देशव्यापी आलोचना की जा रही है। कालांतर यूट्यूब को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बाद इस एपिसोड को हटाना पड़ा था। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसी अश्लील व अभद्र टिप्पणी करने का यह पहला मामला नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अनाप-शनाप बकने का सिलसिला पिछले लंबे समय से सोशल मीडिया पर चल रहा है। दरअसल, कई कॉमेडियन व कलाकार विभिन्न कार्यक्रमों में ऐसी बकवास करते रहते हैं ताकि उन्हें नकारात्मक चर्चा से व्यापक पहचान मिल सके। लगातार कोशिश होती रहती है कि वर्जित विषयों को कार्यक्रमों में शामिल करके तरह-तरह के विवाद खड़े किए जाएं। दरअसल, टीवी चैनल भी टीआरपी के गंदे खेल में ऐसे हथकंडे अपनाने से नहीं चूकते, जो विवाद पैदा करें। ऐसे कॉमेडी कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला है जो अश्लीलता, फूहड़ता और अभद्रता को अपने विषय वस्तु बनाते हैं। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर वर्जना तोड़ते कार्यक्रमों की बाढ़ सी आई हुई है। विडंबना यह कि सोशल मीडिया में संपादक नामक संस्था का कोई स्थान नहीं है जिसके चलते अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देकर तमाम वर्जित विषयों व संवादों को तरजीह दी जा रही है। एक हकीकत यह भी है कि अभद्र, अश्लील, आपत्तिजनक और पोर्नोग्राफिक कंटेंट से सोशल मीडिया कंपनियों को भी मुनाफा होता है। कार्रवाई की मांग किए जाने पर ये विदेशी कंपनियां अमेरिकी कानून को अपना कवच बनाने का प्रयास करती हैं। विगत में भी एक विवाद के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी डिजिटल कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। यद्यपि आईटी मंत्रालय को आपत्तिजनक एप्स और कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया की निरंकुश भूमिका को देखते हुए एक सख्त कानून की जरूरत महसूस हो रही है। इसके अभाव में ऐसे विवादित कार्यक्रम सुर्खियों में आते रहते हैं। हो- हल्ला होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होती है, लेकिन बहुत कम मामलों में आरोपियों को सजा हो पाती है।

ट्रंप भारत के उत्पादों पर भी टैरिफ लगायेंगे ?

ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25 प्रतिशत और चीन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ का एलान किया। इस पर चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया। इससे अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार का नया दौर शुरू हो गया है। वस्तुतः चीन, मेक्सिको और कनाडा से अमेरिका को सबसे ज्यादा व्यापार घाटा होता है।

ये तीनों देश अमेरिका के लगभग 670 अरब डॉलर व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। वर्ष 2023 में अमेरिका को चीन से 317 अरब डॉलर, मेक्सिको से 200 अरब डॉलर और कनाडा से 153 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ था। जबकि अमेरिका के व्यापार घाटे में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 36 अरब डॉलर रही है। हालांकि ट्रंप भारत की ओर से अमेरिकी उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने की शिकायत करते हुए बदले में भारत के उत्पादों पर भी टैरिफ लगाने की बात लगातार कहते आए हैं।

ऐसे में अब उनके द्वारा भारत के उत्पादों पर भी अधिक टैरिफ लगाए जाने की आशंका है। यही कारण है कि भारत ने अपने यहां कुछ अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम करना शुरू कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में भी भारत ने अमेरिका से आने वाली कई वस्तुओं जैसे मोटरसाइकिल, सेटेलाइट के लिए ग्राउंड इंस्टालेशन और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस जैसे कुछ सामानों पर शुल्क घटा दिए हैं। दोनों देशों ने अब एक-दूसरे के लिए उपयुक्त टैरिफ तय करने पर सहमति जताई है।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। उसमें भारत और अमेरिका ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में कारोबार तथा रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने, व्यापार पर गतिरोध के बीच टैरिफ को कम करने, अधिक अमेरिकी तेल एवं गैस और लड़ाकू विमानों की खरीद के बारे में बात करने और रियायतों पर भी सहमति व्यक्त की।

साथ ही भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। भारत और अमेरिका भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के निर्माण के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। ट्रंप ने इसे सबसे बड़े व्यापार मार्गों में से एक बताया और कहा कि यह मार्ग इजरायल से इटली और फिर अमेरिका तक जाएगा।

दरअसल ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में वैश्वीकरण की जगह ह्यमेरा अमेरिका प्रथमह्ल की धारणा को उच्च प्राथमिकता देते हुए आत्मनिर्भरता की डगर पर बढ़ना शुरू कर दिया है। इसके लिए वह सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक शुल्क लगाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाता है, उस पर अमेरिका भी उतना ही टैरिफ लगाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के साथ वार्ता के बाद भारत के लिए चुनौतियों के बीच अवसर भी दिखाई दे रहे हैं।

ट्रंप के पहले शासनकाल में भारत चीन के खिलाफ अमेरिकी सख्ती का फायदा नहीं उठा सका था। ऐसे में अब ट्रंप द्वारा अमेरिकी प्रशासन की बागडोर संभालने के बाद भारत ने द्विपक्षीय वार्ता के साथ-साथ ऐसी बहुआयामी रणनीति पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका के साथ वैश्विक स्तर पर भी भारत के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिल सके।

वस्तुतः ट्रंप की नीति से भारत को चीन प्लस वन के रूप में वैश्विक व्यापार में तेजी से बढ़ने का मौका भी मिलता हुआ दिख रहा है। चीन में मैन्यूफैक्चरिंग करने वाली कई विदेशी कंपनियां भारत का रुख कर सकती हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिन क्षेत्रों में चीन अमेरिका को प्रमुखता से निर्यात करता है, उनमें से कई क्षेत्रों में अमेरिका को भारत अपना निर्यात सरलता से बढ़ा सकता है।

इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मोबाइल फोन, फुटवियर, कपड़ा, फर्नीचर, घर के सजावटी सामान, वाहनों के कलपुर्जे, खिलौने और रसायन आदि शामिल हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय निर्यातकों को अमेरिका बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए आम बजट में घोषित किया गया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अहम भूमिका निभाएगा।

इस मिशन और मार्केटिंग प्रोत्साहन से निर्यातकों को अमेरिका के विभिन्न भागों में आयोजित प्रदर्शनियों में शामिल होने और अमेरिका में निर्यात योग्य नए उभरते क्षेत्रों की संभावनाओं का दोहन करने में मदद मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि जिस तरह ट्रंप अमेरिका प्रथम की रणनीति के साथ अमेरिका को तेजी से आर्थिक मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी भारत प्रथम की रणनीति को आगे बढ़ाकर घरेलू उद्योग, कारोबार और अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के मौके को मुट्ठी में ले सकते हैं।

उम्मीद है मोदी और ट्रंप की वार्ता भारत-अमेरिका के बीच कारोबार बढ़ाने के साथ-साथ चीन प्लस वन के मद्देनजर भारत के लिए वैश्विक स्तर पर अधिक निर्यात के मौके निर्मित करने वाली साबित होगी। भारत और अमेरिका भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे को इजरायल से इटली तक ले जाएंगे। इससे भारत के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। अमेरिका के साथ मजबूत आर्थिक-कारोबारी रिश्ते भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में भी मददगार साबित होंगे।

मोदी युग की भाजपा के उदय के बाद बसपा का सपना ध्वस्त

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1989 के बाद से ही बहुजन समाज पार्टी के एक राजनीतिक स्थिति में बनने की शुरूआत हो गई थी। काशीराम के दौर की राजनीति में जब 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ी तो पहली बार बसपा को 67 सीटें हासिल हुई थीं और सपा-बसपा के गठबंधन ने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया था। लेकिन यह गंठबंधन दूर तक इसलिए नहीं चला क्योंकि इस गठबंधन से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि हमेशा के लिए सपा-बसपा साथ आ जायेंगे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का सत्ता में आ पाना मुश्किल होगा।

मंडल के उभार के बाद कांग्रेस और भाजपा को लगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कहीं पश्चिम बंगाल जैसी न हो जाये जहां लम्बे अर्से तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा और कांग्रेस सत्ता में तबसे नहीं आ पायी। इसलिए दोनों ही पार्टियों की ओर से इस गठबंधन को तोड़ने के लिए तरह-तरह के प्रयास किए जाते रहे और ऐसी स्थिति आ गई कि बसपा ने समर्थन वापस ले लिया और उसके बाद जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनीं उससे गेस्ट हाउस जैसा कांड इतिहास में दर्ज हो गया।

भाजपा ने 67 सदस्यों वाली बसपा को बाहर से समर्थन देकर सरकार बनवाई और राजभवन में हो रहे बसपा की इस सरकार के शपथ ग्रहण में 'जय श्रीराम' के नारे लगे। कांग्रेस चाहती तो उस समय प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी हो सकता था लेकिन कांग्रेस को लगा कि यदि वह बसपा की सरकार बनवा देगी तो वह दलित वोट उसके पास आ जायेगा और बसपा के साथ गठबंधन करके बाद सता का समीकरण उत्तर प्रदेश में ठीक कर लेगी। क्योंकि मंडल-कमंडल की राजनीति और अयोध्या आंदोलन की वजह से कांग्रेस का वोट आधार ही छिटक गया। यही कारण है कि 1989 के लोकसंभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जब दो दिवसीय दौरे पर अपने निर्वाचित क्षेत्र रायबरेली आये तो उन्होंने दलित छात्रों के साथ संवाद में कहा कि यदि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती साथ देतीं तो उत्तर प्रदेश से भाजपा साफ हो जाती। उन्होंने यह भी कहा कि पता नहीं क्यों मायावती चुनाव नहीं लड़ रही हैं। यदि उत्तर प्रदेश में सपा, कांग्रेस और बसपा एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ती तो भाजपा उत्तर प्रदेश से साफ हो जाती। उन्होंने कहा कि मायावती भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रहीं हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वक्तव्य के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भी कांग्रेस को जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी शासित राज्यों में या जहां कांग्रेस मजबूत है वहां बसपा के समर्थकों के साथ जातिवादी रवैया अपनाया जाता है और दिल्ली के चुनाव परिणाम को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा कि दिल्ली में कांग्रेस चुनाव लड़कर क्या भाजपा की बी टीम नहीं बनी है।

जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है?

उत्तर प्रदेश के नौ विधानसभा उपचुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी तो सपा का कहना था कि बसपा की वजह से हारे। लेकिन जब नौ उपचुनाव के परिणाम आये तो बसपा ने उपचुनाव से एक बार पिर से तौबा कर ली और जब मिल्कीपुर में उपचुनाव में सपा हार गई तो उनका यही कहना था कि जब बसपा चुनाव नहीं लड़ी तो सपा क्यों हार गई?

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार बसपा के साथ गठबंधन करने के लिए प्रयासरत रही जिसकी वजह से वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने में देरी करती रही। उसकी पहली प्राथमिकता बसपा ही थी। उसे लगता था कि यदि बसपा के साथ उसका गठबंधन हो गया तो मुसलमान वोट उसे अपने आप ही मिल जायेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अभी भी कांग्रेस बसपा के साथ अच्छा सम्बन्ध बनाने की पक्षधर है जिससे उसे उत्तर प्रदेश में एक आधार आगे बढ़ने के लिए मिल सके क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा वोट अभी भी बसपा के पास है। यही कारण है कि

कांग्रेस का बसपा के प्रति नरम व्यवहार रहा है। बसपा तभी कांग्रेस के साथ आ सकती है जब उसे लगे कि वह उसके कंधे पर बैठकर सत्ता में आ सकेगी। मोदी युग की भाजपा के उदय के बाद बसपा का सपना धराशायी हो गया जब 2014 में उसे लोकसभा में एक भी सीट हासिल नहीं हुई। तब 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी और दस लोकसभा की सीटें झटक लीं जबकि सपा पांच पर ही सिमटी रहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एकला चलो के नारे ने बसपा को फिर 2014 की स्थिति में ला दिया जब उसके हाथ एक भी सीट नहीं लगी और मत प्रतिशत अलग से गिर गया। बसपा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो त्रिकोण पैदा किया था अब उसका शीराजा बिखर रहा है।

मायावती के बार-बार अपने ही निर्णयों को बदलने के कारण उसके कार्यकर्ता भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बसपा की आखिर रणनीति और राजनीति क्या रहेगी ? यही कारण है कि उसके नेता और कार्यकर्ता जो कभी बहनजी की किचन कैबिनेट का हिस्सा होते थे सपा और भाजपा में चले गए हैं और वहां से विधायक और सांसद निर्वाचित हो रहे हैं।

राहुल गांधी का यह कहना कि यदि बसपा साथ आती तो उत्तर प्रदेश से भाजपा साफ हो जाती लेकिन ठीक इसका उल्टा भी हो सकता था कि यदि वे कुछ सीटें जीत भी जाती तो क्या गारंटी थी कि वह भाजपा के साथ सरकार बनाने न चली जाती? ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस के साथ बसपा ने गठबंधन नहीं किया, लेकिन सरकार किसके साथ बनायी, कांग्रेस को यह भी आंकलन कर ही लेना चाहिए।

जिला कारागार प्रांगण में कवि सम्मेलन का आयोजन

करनाल । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नशे को लेकर जिला कारागार करनाल प्रांगण में राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन का आयोजन करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉ इरम हसन सी जे एम व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रही, कार्यक्रम में विशेष तौर पर कारागार अधीक्षक लखबीर सिंह बराड़ रहे, उपाधीक्षक चरण सिंह,डी एस पी सैलाक्षी भारद्वाज,एम डी डी बाल भवन संस्थापक पी आर नाथ, सचिव रेड क्रास सोसायटी कुलबीर मलिक व नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े अशोक कुमार रहे। कवि सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ इरम हसन,कारागार अधीक्षक लखबीर सिंह बरार द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया,इस कवि सम्मेलन में दिल्ली व हरियाणा के कवि शायरों ने हिस्सा लिया,कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कैदियों को नशे के प्रति जागरूक करना रहा, जिसमें कविताओं, गजलों, हास्य व्यंगों व गीतों द्वारा समां बांधा गया,कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ इरम हसन ने कहा नशा है आग नशा है जहर, धीरे धीरे खाए हर पहर, तन को तोड़े मन को झुलसाए,हर सुख शांति दूर भगाए, उन्होंने प्रत्येक इंसान को नशे से दूर रहने की बात भी कही,वरिष्ठ शायर डॉ एस के शर्मा ने कहा कैसे कैसे दिन दिखाएं नशे के इस रोग न बाप की पगड़ी धूल चटाई दी एक नशेड़ी बेटे ने,कार्यक्रम की सदारत कर रहे कवि प्रेम पाल सागर ने कहा मेरी बबार्दी का सबब यारो ये शराब है, सांस भी ले नहीं सकता इस कदर हालात खराब है, कार्यक्रम के संयोजक व मन की उड़ान साहित्यिक मंच करनाल के संस्थापक रामेश्वर देव ने कहा जो मिट गया नशे में घर अच्छा नहीं होता, बबार्दीयों का वो सफर अच्छा नहीं होता, वरिष्ठ शायर इकबाल पानीपती ने सुल्फा गांजा भांग धतूरा हीरोइन स्मेक शराब,जिसको इसकी लत लग जाए हो जाए खाना खराब, दिल्ली से पधारी कवयित्री सीमा रंगा इंद्रा ने कहा तेरा जीवन तेरा है बस भेंट चढ़ाओ क्यों तुम,लिया नशा जीवन में तूने तो हो जाओगे गुम*,रोहतक से पहुंचे कवि डॉ सतबीर सिंह निराला ने कहा दुनिया में दोस्त कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं,पीते हैं शराब और दोस्त को पिलाते हैं,दिल्ली से पधारी कवयित्री डॉ सन्तोष संप्रीति ने कहा तन मन धन सब लुटता नशा नाश का मूल,भूल कर भी मत करना नशा करन की भूल,कवयित्री अंजू शर्मा ने कहा नशे नै ठाई तबाही कूण ससुर कूण जमाई,रोज रोज पंचायत होरी बेटी घर नै उल्टी आई, झज्जर से आए कवि जय सिंह जीत ने कहा भले इंसान तेरी जिन्दगी नाशाद कर देगा, नशे को छोड़ दो ये आपको बर्बाद कर देगा, कवि सुरेश भाणा ने कहा नशा करै बुरी दशा क्रोध का बाप बताया जा, क्रोध खत्म करै बुद्धि न हो खत्म मानस की काया जा,रेड क्रास सोसायटी सचिन कुलबीर मलिक ने भी सोसाइटी द्वारा किये जा कार्यों को बताया,अशोक वर्मा में व्यापक तौर पर नशे की उपस्थिति समूह से चर्चा की ओर बहुत से पहलुओं पर प्रकाश डाला,कार्यक्रम के समापन अवसर पर कारागार अधीक्षक लखबीर सिंह बराड़ ने मुख्य अतिथि डॉ इरम हसन व सभी कवियों, कवयित्रियों शायरों का धन्यवाद किया और कहा कि आज के नशे को लेकर कार्यक्रम सफल रहा और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी सभागार में समय समय पर करवाएं जाएंगे,कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक मन की उड़ान साहित्यिक मंच करनाल संस्थापक रामेश्वर देव ने किया,मुख्य अतिथि,विशेष अतिथियों कवियों, कवयित्री शायरों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया।

प्रस्तुति : सीमा रंगा इन्द्रा

साफ होनी चाहिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर दिमागी गंदगी ?

कुछ लोग ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। ऐसा कंटेट प्रसारित कर रहे हैं जो चिंता का विषय है। विवाद बढ़ने के बाद ये अश्लील इंफ्लूएंसर अपनी करतूत पर माफी मांग लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनकी शर्मनाक हरकत पर इनका माफी मांग लेना काफी है या बड़ा एक्शन होना चाहिये? ऐसे लगों को कानूनी तौर पर तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही में जनता उनके सभी चैनलों का बहिष्कार करेगी तो यह उनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। इन लोगों को सजा मिलनी आवश्यक है तभी बाकी इस प्रकार के मानसिक दिवालिया वाले लोग सुधार पाएंगे। ऐसे सारे कार्यक्रम, ओटीटी, टीवी, आदि पर भी हैं। सब बंद होना चाहिए। ऐसा बलगर कंटेंट्स हमारे देश की संस्कृति को खत्म कर देगी।.यह निंदनीय है और सभ्य समाज के लिए गलत भी। ऐसे लोग हमारा सनातन धर्म और हिंद संस्कृति का बेड़ागर्क कर रहे है। इनको सजा होनी चाहिए ताकि आने वाले समय ऐसी नीच हरकत और सोच रखने वाले ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचना पड़े। इस सब प्रकार की घिनौनी मानसिकता को देखना और सुनना आज के समाज का भी कसूर है। इन जैसे लोगों का समाज से बहिष्कार करना चाहिए। गंदी भाषा वाले बहुत सारे नाटक और फि ल्में दिखाई जाती हैं। उन्हें भी बंद कर देना चाहिए। ओटीटी पर तो बहुत ज्यादा अश्लीलता परोसी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर 'आपत्तिजनक' टिप्पणियों की निंदा की। सर्वोच्च न्यायालय ने अल्लाहबादिया के शब्दों के पीछे छिपे गहरे मुद्दों को उजागर करते हुए इसे ₹उनके दिमाग की गंदगी₹ कहा। अल्लाहबादिया के शब्दों की निंदा करते हुए कहा कि उसकी भाषा से माता-पिता और बहनों को शर्म आएगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अल्लाहबादिया की टिप्पणियों की विकृत प्रकृति से ₹पूरा समाज शर्मिंदा महसूस करेगा₹। यह मामला डिजिटल युग में प्रभावशाली व्यक्तियों और सामग्री निमार्ताओं की जिम्मेदारी के बारे में व्यापक चर्चा को जन्म देता है। वैसे भी सार्वजनिक हस्तियों को अपनी भाषा के प्रयोग के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक मूल्यों पर असर पड़ता है। समाज पर ऐसे युवा प्रतीकों के प्रभाव को कम आंकना मूर्खतापूर्ण होगा, विशेषकर युवा मस्तिष्कों और स्वस्थ समाज की बुनियादी संस्कृति पर। क्या यह काफी बड़ा नहीं है? यह पूछना कि शो का कोई प्रतियोगी किस चीज के लिए कितना शुल्क लेगा, क्या इससे युवाओं की एक पूरी पीढ़ी भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? तर्कहीन ढंग से और समाज के प्रति किसी जिम्मेदारी के बिना कही गई बातें। क्या आपके बच्चे नहीं हैं और न ही आपको उनकी परवाह है। सच तो यह है कि ह्यमजाकह्व के माध्यम से ऐसी अश्लीलता को सामान्य बनाना उसी मानसिकता को बढ़ावा देता है जो वास्तविक अपराधों को बढ़ावा देती है। समाज रातों-रात नहीं बिखर जाता - इसकी शुरूआत असहनीय को सहन करने, घृणित को ह्लसिर्फ हास्यह्व के रूप में नजरअंदाज करने और धीरे-धीरे नैतिक सीमाओं को खत्म करने से होती है। कानूनी कार्रवाई का मतलब सिर्फ व्यक्तियों को दंडित करना नहीं है। इसका उद्देश्य एक मिसाल कायम करना है कि कुछ चीजें स्वीकार्य नहीं हैं, चाहे लोग उन्हें कितना भी हास्यपूर्ण बताने की कोशिश करें। यदि वे सचमुच समाज को बेहतर बनाने के बारे में चिंतित हैं, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि सांस्कृतिक पतन से लड़ना भी बड़े अपराधों से निपटने जितना ही महत्वपूर्ण है। यदि आप सोचते हैं कि हमें ऐसे घृणित ह्यमजाकह्व को नजरअंदाज कर देना चाहिए और केवल ह्यवास्तविक अपराधोंह्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो आप यह समझने में विफल हैं कि समाज कैसे काम करता है। विकृत और अपमानजनक हास्य को सामान्य मानने से नैतिक सीमाएं कमजोर होती हैं और लोग अस्वीकार्य चीजों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। कॉमेडी में बिना किसी परिणाम के कुछ भी कहने की छूट नहीं है। खासकर तब जब यह बहुत ही विचलित करने वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। कानून गरिमा को बनाए रखने और बुनियादी शालीनता के क्षरण को रोकने के लिए मौजूद हैं। अगर आप ह्यहह सिर्फ.एक मजाक हैह्व के नाम पर इसका बचाव कर रहे हैं, तो शायद असली मुद्दा यह है कि आप इस तरह की सामग्री के प्रभाव के प्रति कितने सुन्न हो गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। आपका यह तर्क कि हमें 'मजाक के बजाय वास्तविक अपराधों और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए' मूर्खतापूर्ण और अपरिपक्व दोनों है। हास्य में शक्ति होती है और शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। 'मजाक' कहलाने वाली हर बात हानि रहित नहीं होती। कुछ हास्य हानिकारक व्यवहार को सामान्य बना देता है। यदि कोई मजाक अनादर, असंवेदनशीलता या नैतिक सीमाओं को लांघने पर आधारित है, तो यह सवाल उठना उचित है कि क्या यह समाज का उत्थान करता है या पतन करता है। आलोचना का मतलब 'घटिया मानसिकता' रखना नहीं है; यह संस्कृति पर विषय-वस्तु के प्रभाव को पहचानने के बारे में है। यदि कॉमेडी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता तो फिर वास्तव में संवेदनशील कौन है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसी सामग्री का बचाव करना केवल यह साबित करता है कि समाज में क्या स्वीकार्य है, इसके प्रति लोग कितने असंवेदनशील हो गए हैं। स्वतंत्रता का अभिप्राय है, सही समय पर सही यानि नैतिक कार्य करने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिप्राय है- उचित समय पर उचित बात कहने की स्वतंत्रता। इसके विपरीत कुछ भी, कभी भी कह देने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता को ही अराजकता कहा जाता है। अतः स्वतंत्रता एक कानूनी प्रक्रिया है, इसके विपरीत स्वच्छंदता गैरकानूनी है। अतः अभिव्यक्ति की कानूनी स्वतंत्रता के तहत अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता की अनुमति गैरकानूनी है। अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता को प्रश्रय, सोशल मीडिया की गुणवत्ता की जगह मात्रा को अहमियत देने की व्यवस्था ने दिया है। लोग ज्यादा व्यूज के लिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। अगर यूट्यूब, मात्रा की अपेक्षा गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करे, तो ऐसे ओछे प्रयास बंद हो जायेंगे। आजकल लोग किसी भी तरह से पैसा और शोहरत हासिल करना चाहते हैं। और इस तरह की उत्तेजना पैदा करने वाली बातें युवा वर्ग को आकर्षित करती हैं। इसलिए लोग इस तरह के भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। वृक्ष की पहचान उसके फल से होती है और माता पिता की पहचान उसके संतान से होती है। इनके माता-पिता का परिचय मिल गया है। कीड़े लगा वृक्ष, कीड़े लगा फल ही देगा। यह पैसा ही वह कारण है जो इन बेगैरत शोहदों को उनके माता-पिता द्वारा खुली छूट देने देता है। इनके माता-पिता को इनकी बेशर्म अदाओं पर कोई ऐतराज इसीलिए नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें इससे अच्छा खासा पैसा मिलता है। अगर इनके माता-पिता को ऐतराज होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती।

-प्रियंका सौरभ

कैदियों की समय से पहले रिहाई से समाज को खतरा हो सकता है, खासकर तब जब वे बार-बार अपराध करते हों। हाल के वर्षों में, इस विचार में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है क्योंकि अमीर और शक्तिशाली वर्ग ने जेल में समय बिताने से बचने के लिए पैरोल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, लाखों अन्य कैदी, जिनके पैरोल के अनुरोधों को अनदेखा किया जाता है, उनके पास प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए संसाधनों की कमी होती है, या उन्हें कमजोर आधारों के आधार पर गलत तरीके से लाभ से वंचित किया जाता है क्योंकि वे गरीब और शक्तिहीन हैं।

क्या जघन्य अपराधियों की न सुनी जाये पैरोल की अर्जी?

पैरोल सुधार और पुनः एकीकरण पर आधारित है, लेकिन जब इसका उपयोग गंभीर अपराधों के लिए किया जाता है, तो यह नैतिक और कानूनी दुविधाएँ पैदा करता है। मानवाधिकारों और पुनर्वास के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, भले ही न्याय दंड और रोकथाम की मांग करता हो। आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण कदम पैरोल है। यह कैदियों को समाज में पुनः एकीकृत करने में सहायता करने के लिए दिया जाने वाला एक प्रकार का विचार है। यह कैदी की सामाजिक पुनर्प्राप्ति के लिए एक उपकरण से अधिक कुछ नहीं है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, इस विचार में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है क्योंकि अमीर और शक्तिशाली वर्ग ने जेल में समय बिताने से बचने के लिए पैरोल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, लाखों अन्य कैदी, जिनके पैरोल के अनुरोधों को अनदेखा किया जाता है, उनके पास प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए संसाधनों की कमी होती है, या उन्हें कमजोर आधारों के आधार पर गलत तरीके से लाभ से वंचित किया जाता है क्योंकि वे गरीब और शक्तिहीन हैं। चूँकि हमारी जेलें अहिंसक अपराधियों से सचमुच भरी हुई हैं, इसलिए पैरोल से जेल में बंद लोगों को अपने प्रियजनों के साथ अपनी सजा के बचे हुए हिस्से को पूरा करने का मौका मिलता है, जबकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की उन पर कड़ी नजर रहती है। यह हर दिन लाखों रुपयों की टैक्स बचत करता है और पूरे समाज के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था है। बहुत कम बार आप किसी हिंसक अपराधी के बारे में सुनते हैं जो पैरोल पर रिहा हुआ और फिर एक और हिंसक अपराध करने लगा।

ज्यादातर हिंसक अपराधी किसी भी मामले में अपनी सजा का कम से कम 85% हिस्सा पूरा करते हैं। लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि पैरोल से पीड़ितों और उनके परिवारों की न्याय की भावना कमजोर हो सकती है। आतंकवाद, बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ मजबूत रोकथाम होनी चाहिए। रोकथाम बनाए रखने के लिए, 2012 के निर्भया मामले के दोषियों को पैरोल नहीं दी गई। कैदियों की समय से पहले रिहाई से समाज को खतरा हो सकता है, खासकर तब जब वे बार-बार अपराध करते हों। बार-बार अपराध करने के कारण, 2013 के शक्ति मिल्स सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों को पैरोल नहीं दी गई। राजनीतिक प्रभाव से न्याय में विश्वास को नुकसान हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप पैरोल की मंजूरी मिलती है जो वारंटेड नहीं होती है। टी. पी. चंद्रशेखरन हत्या मामले में पैरोल कथित तौर पर राजनीतिक दबाव के कारण दी गई थी। इन अपराधों में शामिल क्रूरता और पूर्व-योजना के कारण, सुधार चुनौतीपूर्ण है। 2018 के कठुआ बलात्कार मामले ने स्पष्ट कर दिया कि दया से रहित कठोर दंड की आवश्यकता है। भारतीय न्यायालयों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पैरोल पर रिहा किए गए लोगों को संतानोत्पत्ति और विवाह के अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति है। हालाँकि, चूँकि विवाह के अधिकार को कानून द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए इस आधार पर पैरोल देने से समलैंगिक कैदियों के समानता के अधिकार से समझौता होता है।

सभी कैदियों के लिए समानता और समावेशिता की गारंटी देने के लिए, न्यायालय अनुच्छेद 21 के तहत अंतरंगता के अधिक सामान्य अधिकार से पैरोल को जोड़ सकते हैं। नेल्सन मंडेला नियम (2015), कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, का एक प्रमुख घटक सुधार है। पैरोल एक अधिकार है, न कि विशेषाधिकार, जैसा कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कई फैसलों में जोर दिया है। सामान्य प्रतिबंध होने के बजाय, व्यवहार मूल्यांकन के आधार पर पैरोल दी जानी चाहिए। आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों के पुनर्वास के परिणामस्वरूप 2023 में महाराष्ट्र में पुनरावृत्ति में कमी आई। पैरोल अनुरोधों का मूल्यांकन न्यायालयों द्वारा पहले से ही योग्यता के आधार पर किया जाता है, जिससे सुरक्षा और न्याय की गारंटी मिलती है। हरियाणा राज्य बनाम जय सिंह (2003) में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि पैरोल निष्पक्ष मानकों के अनुसार दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 21 (सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार) का उल्लंघन पैरोल की संभावना के बिना जेल में आजीवन कारावास द्वारा किया जा सकता है, यदि सुधार प्रदर्शित किया जाता है। श्रीहरन (2015) के अनुसार, किसी को पैरोल से पूरी तरह से वंचित करना असंवैधानिक है। नॉर्वे जैसे देशों में धीरे-धीरे पुनः एकीकरण पर जोर देकर, यहाँ तक कि जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों के लिए भी पुनः अपराध दर कम हो गई है। पुनर्वास न्याय के अपने मॉडल की बदौलत नॉर्वे में दुनिया में पुनरावृत्ति की सबसे कम दरें हैं।

जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, मजबूत प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव से पैरोल प्रशासन की प्रभावशीलता बाधित हुई है। कार्यक्रम के लक्ष्य से नियमित रूप से समझौता किया जाता है और कई अनुचित अपराधियों को प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में पैरोल दी जाती है। पैरोल के सम्बंध में, एक अच्छी तरह से परिभाषित न्यायिक नीति आवश्यक है और किए गए कार्यकारी कर्तव्यों की अदालतों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। हमारे कानून निमार्ताओं के लिए हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक बदलाव करने का समय आ गया है। इन बदलावों में कैदियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रगतिशील तरीके से पर्यवेक्षित रिहाई प्रणाली को लागू करने के लिए मजबूत दिशा-निर्देश बनाना, लगातार पैरोल कानून बनाकर यह साबित करना कि यह पुनर्वास के लिए एक प्रभावी उपकरण है और भारत में पैरोल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जाँच और संतुलन स्थापित करना शामिल होना चाहिए। सरकार को जेलों में भीड़भाड़ के बारे में चिंतित होना चाहिए और उन्हें तुरंत इस पर गौर करना चाहिए। भयानक अपराधों के लिए पैरोल को सीमित करते समय न्याय, निवारण और पुनर्वास सभी पर विचार किया जाना चाहिए। सख्त न्यायिक निगरानी के साथ पारदर्शी, योग्यता-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग कर-के व्यापक प्रतिबंधों के बिना सार्वजनिक सुरक्षा और नैतिक निष्पक्षता की गारंटी दी जा सकती है। पैरोल एक ऐसी चीज है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जैसा कि स्पष्ट है।

- डॉ. सत्यवान सौरभ,

महिलाओं के लिए डिफॉल्ट कैरियर विकल्प के रूप में शिक्षण कार्य

प्राथमिक सरकारी स्कूलों में लगभग एक-तिहाई शिक्षकों के पास आवश्यक शिक्षण डिग्री नहीं है केवल 46% प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पास उचित योग्यता है, जैसे कि शिक्षा में डिप्लोमा या शिक्षा स्नातक। पिछले कुछ वर्षों में, भारत में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों और निजी ट्यूटर्स के रूप में काम करने वाले अयोग्य शिक्षकों की संख्या बच्चों के शुरूआती वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में चिंता का एक प्रमुख कारण रही है। यह घटना न केवल छोटे बच्चों के मूलभूत सीखने से समझौता करती है, बल्कि उनके शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास के लिए दीर्घकालिक निहितार्थ भी है। भारत में, अधिकांश शिक्षक महिलाएं हैं, क्योंकि इसे महिलाओं के लिए डिफॉल्ट कैरियर विकल्प के रूप में माना जाता है। यह एक प्रचलित सामाजिक धारणा के कारण सबसे अधिक संभावना है कि यदि कोई महिला औपचारिक क्षेत्र में काम नहीं कर रही है या घरेलू काम कर रही है, तो उसे अपनी योग्यता या पेशे के प्रति झुकाव के बावजूद, शिक्षण या घर के ट्यूशन का विकल्प चुनना चाहिए। इसका कारण यह है कि यह मजबूत विश्वास है कि शिक्षण महिलाओं के लिए एक आसान और उपयुक्त पेशा है, जो बहुत कम प्रयास की मांग करता है लेकिन उन्हें अपने घरों की दीवारों के भीतर रहने में सक्षम बनाता है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (युडीआईएसई+) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में शिक्षकों का एक बड़ा प्रतिशत पेशेवर रूप से योग्य नहीं है। समस्या औपचारिक शिक्षा से परे निजी ट्यूशन के डोमेन से परे है। निजी ट्यूशन भारत में एक आम बात है, जिसमें कक्षा 1 से 8 में लगभग एक-पांचवें ग्रामीण बच्चों के साथ निजी ट्यूशन के लिए जा रहे हैं। यह उच्च वर्गों या शहरी क्षेत्रों में प्रतिबंधित नहीं है; उदाहरण के लिए, ग्रामीण पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में, प्राथमिक स्तर पर 75% बच्चों के करीब निजी ट्यूशन मिलते हैं। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल (एनआईओएस) से एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक सरकारी स्कूलों में लगभग एक-तिहाई शिक्षकों के पास आवश्यक शिक्षण डिग्री नहीं है। बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, यह प्रतिशत और भी अधिक है, जिसमें 50% से अधिक शिक्षकों में औपचारिक शिक्षण योग्यता की कमी है। इसके अतिरिक्त, लगभग 45% अनियमित स्कूल योग्य शिक्षकों के बिना काम करते हैं, स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में शैक्षिक मानकों को बनाए रखने में चुनौतियों को उजागर करते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के लिए शिक्षा प्लस (युडीआईएस शई+) की एक रिपोर्ट बताती है कि सभी स्कूलों में लगभग एक चौथाई शिक्षकों के पास केवल उच्च माध्यमिक शिक्षा है, और कुछ स्नातक भी नहीं हैं। औपचारिक प्रशिक्षण की इस कमी का उनके शिक्षण प्रभावशीलता पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि अप्रशिक्षित शिक्षकों में बुनियादी शैक्षणिक कौशल की कमी होती है, जो छात्रों के सीखने के परिणामों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। दीर्घकालिक परिणाम स्कूली शिक्षा के शुरूआती

वर्षों में अयोग्य शिक्षकों के लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव हो सकते हैं: गरीब शैक्षिक फाउंडेशन: प्राथमिक वर्षों में खराब शिक्षण से बुनियादी कौशल में अंतराल होता है जो छात्रों के लिए उच्च ग्रेड पर परिष्कृत विचारों का प्रबंधन करना मुश्किल बनाता है। कम प्रेरणा और आत्मविश्वास: सीखने के साथ चल रही कठिनाई से निराशा हो सकती है और आत्मविश्वास कम हो सकता है, जो शिक्षा के प्रति छात्रों के सामान्य दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। प्रतिबंधित भविष्य के अवसर: एक समझौता प्राथमिक शिक्षा प्रमुख परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन में बाधा डाल सकती है, इस प्रकार उच्च शिक्षा और नौकरी तक उनकी पहुंच को सीमित कर सकती हैअवसर।

राष्ट्रीय अवलोकन: 2023 तक, भारत में लगभग 94.94% प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने न्यूनतम आवश्यक पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 2022 में यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 88.68% से वृद्धि को चिह्नित किया है। राज्य-विशिष्ट आंकड़ा नागालैंड: यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 30% प्राथमिक शिक्षकों में आवश्यक योग्यता की कमी है, जो कि 4.56% की राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। महाराष्ट्र: केवल 46% प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पास शिक्षण में डिप्लोमा या बैचलर ऑफ एजुकेशन जैसी उचित योग्यताएं हैं, जो कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन टीचर एजुकेशन (सीईटीई) द्वारा रिपोर्ट के अनुसार हैं। सार्वजनिक बनाम निजी स्कूल: निजी क्षेत्र अयोग्य शिक्षकों के उच्च अनुपात को नियोजित करता है। महाराष्ट्र में, लगभग 87% अयोग्य शिक्षक निजी स्कूलों में हैं।

क्षेत्रीय असमानताएं: मेघालय और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में क्रमशः 33.91% और 51.65% पर अयोग्य प्राथमिक शिक्षकों का उच्च प्रतिशत है।

ये आँकड़े शिक्षक प्रशिक्षण और योग्यता को बढ़ाने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों के लिए दबाव की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों और स्कूल प्रकारों में जहां कमियों को सबसे अधिक स्पष्ट किया जाता है। भारत बनाम यूएस भारत और अमेरिका में एक शिक्षक बनना बहुत अलग है, अलग-अलग शिक्षा नीतियों, प्रमाणन आवश्यकताओं और सामाजिक मूल्यों का एक कार्य। भारतीय प्राथमिक स्कूलों में गुणवत्ता वाले शिक्षकों की कमी एक दबाव वाला मुद्दा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक योग्यता शैक्षिक स्तरों, राज्य प्रमाणन आवश्यकताओं और निरंतर व्यावसायिक शिक्षा के मिश्रण पर आधारित हैं। नीचे प्रमुख बिंदुओं का सारांश है:

भारत बनाम अमेरिका: प्रमाणन आवश्यक है स्नातक की डिग्री आवश्यकता: प्रत्येक सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। राज्य द्वारा जारी प्रमाणन: डिग्री के अलावा, प्रशिक्षकों को पब्लिक स्कूल निर्देश के लिए राज्य द्वारा जारी प्रमाणन या लाइसेंस को सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है। यह एक मान्यता प्राप्त शिक्षक के शिक्षा कार्यक्रम को पूरा करने और एक प्रासंगिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर जोर देता है। भारत बनाम यूएस: जनसांख्यिकी और अनुभव लिंग वितरण: प्राथमिक स्तर पर शिक्षण पेशेवरों की महिला-से-पुरुष लिंग वितरण महिलाओं को सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 89% शिक्षकों को बनाते हुए दिखाता है। रेस एंड एथनिक अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व: 2020-21 स्कूल वर्ष तक, सार्वजनिक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक के 80% गैर-हिस्पैनिक गोरे थे, 9% हिस्पैनिक, 6% काले और 2% एशियाई अमेरिकी थे। भारत बनाम अमेरिका: शिक्षक की तैयारी और गुणवत्ता प्रमाणन की स्थिति: अधिकांश पब्लिक स्कूल शिक्षक पूरी तरह से प्रमाणित हैं। जिला स्तर पर कुछ अंतर हैं। उदाहरण के लिए, ह्यूस्टन इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने अक्टूबर 2023 में 12% से अक्टूबर 2024 में 12% से अप्रमाणित शिक्षकों में वृद्धि की सूचना दी।

विषय - वस्तु विशेषज्ञ: यद्यपि प्राथमिक शिक्षकों को आमतौर पर एक सामान्य ज्ञान का आधार होने की उम्मीद की जाती है, विशेष रूप से विषय वस्तु विशेषज्ञता माध्यमिक स्तर पर तेजी से महत्वपूर्ण हो जाती है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका शिक्षा की समान गुणवत्ता की गारंटी के लिए शिक्षक प्रमाणन के एक औपचारिक और विनियमित मॉडल को प्राथमिकता देता है, भारत में एक दोहरी प्रणाली है। इसमें सरकार की औपचारिक आवश्यकताएं और स्वीकार किए गए स्कूलों और कम औपचारिक, अनियमित डोमेन दोनों शामिल हैं, जहां कोई आवश्यक योग्यता के बिना शिक्षक की भूमिका निभा सकता है। द्वंद्व मौजूद है क्योंकि यह अधिक सामान्य सामाजिक-आर्थिक बलों का प्रतिनिधि है और अलग-अलग शिक्षा की गुणवत्ता को मानकीकृत करने की कठिनाई को दर्शाता हैजी संदर्भ। अच्छी तरह से प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों को भारत के बच्चों के लिए एक मजबूत शैक्षिक मंच प्रदान करने के लिए औपचारिक शिक्षा और निजी ट्यूशन दोनों का प्रमुख होना चाहिए। यह केवल नीति का सवाल नहीं है, बल्कि देश के भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।

विजय गर्ग
मलोट पंजाब

वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या

भारत समेत कई एशियाई देशों में वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका, बैंकॉक और जकार्ता जैसे शहरों में लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं ।एनजी पॉलिसी इंस्टिट्यूट ऑफ शिकागो की तनुश्री गांगुली कहती हैं, 'सबसे पहले यह समझना होगा कि हवा सिर्फ तभी प्रदूषित नहीं होती, जब धुंध छाई रहती है। नीला आसमान हवा के साफ होने की गारंटी नहीं देता।'

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, दुनिया की लगभग 99 फीसदी आबादी कभी ना कभी ऐसी हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होती है, जो डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुरूप नहीं होती। डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष प्रदिषत हवा में सांस लेने के चलते 70 लाख लोगों की असमय मौत हो जाती है। वायु प्रदूषण दुनियाभर में समय से पहले होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इसकी वजह से हर साल 70 लाख लोगों की असमय मौत हो जाती है। बच्चों को भी इससे खासा नुकसान होता है। हवा को प्रदूषित करने वाले तत्व अक्सर विभिन्न चीजों को जलाने से पैदा होते हैं। जैसे, बिजली बनाने या परिवहन के लिए कोयला, प्राकृतिक गैस या डीजल-पेट्रोल जैसे ईधन को जलाने से प्रदूषक तत्व वातावरण में जाते है। पराली जलाने और जंगल में लगने वाली आग से भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, लोगों के स्वास्थ्य के लिए पार्टिकलेट मैटर (पीएम) सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये बेहद सूक्षम कण होते हैं, जो सांस के जरिए शरीर में घुस जाते हैं। ईधन जलाने से पैदा होने वाले पीएम 2.5 कण तो फेफड़ों तक में जा सकते हैं। वहीं, खेती, परिवहन और खनन जैसी गतिविधियों से पैदा होने वाले पीएम 10 कण खांसी-जुकाम जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। वायु प्रदूषण दुनियाभर में समय से पहले होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है।

हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों का सबसे ज्यादा बोझ दक्षिण एशिया और अफ्रीका के देशों पर पड़ता है ।कम समय के लिए प्रदूषित हवा में सांस लेने से अस्थमा और दिल का दौरा पड़ने का खतरा होता है। बुजुर्गों और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए यह खतरा सबसे ज्यादा होता है। वहीं, लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से हृदय और फेफड़ों से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिनसे जान भी जा सकती है।

बच्चों के लिए काम करने वाले संगठन युनिसेफ के मुताबिक, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में 50 करोड़ से ज्यादा बच्चे प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं इसके अलावा, प्रति दिन औसतन पांच साल से कम उम्र के 100 बच्चों की मौत होती है, जिस-ाका संबंध प्रदूषण से होता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, हवा के प्रदूषित होने पर घर में ही रहने की कोशिश करनी चाहिए और बाहर निकलने पर मास्क लगाना चाहिए। हालांकि, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टिट्यूट में हवा की गुणवत्ता पर शोध करने वाले डैनी जारुम कहते हैं कि घर के भीतर रहना हमेशा

संभव नहीं होता, खासकर उन लोगों के लिए जो खुले में काम करते हैं। लोगों के घर के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण से भी सावधान रहना चाहिए। घर में होने वाली आम गतिविधियों जैसे खाना पकाने और अगरबत्ती जलाने से भी हवा प्रदूषित होती है। एयर प्यूरिफायर घर के अंदर की हवा को साफ करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है। एयर प्यूरिफायर तभी प्रभावी होते हैं, जब वे छोटी जगहों पर इस्तेमाल किए जाएं और लोग उसके आसपास ही रहें।

मातृभाषा में लोक संस्कृति की झलक

दैनिक जीवन में बढ़ते तकनीकी उपकरणों, आर्थिक सुदृढ़ता के लिए हम पलायन करें, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी मां से दूर जीते-जी नहीं होते। फिर मातृभाषा से दूरी क्यों हो? अपने यहां एक कहावत काफी प्रचलित है कि, ह्यकोस-कोस पर बदले पानी चार कोस पर बानी !ह्न ऐसे में कहा जा सकता है कि मातृभाषा में ही लोक संस्कृति यानी लोककला, लोकगायन, लोकनृत्य, लोकोचार, रीति-रिवाज, परम्पराएं सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं। मातृभाषा ही भाषायी सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक आदि विविधताओं को अक्षुण्ण बनाए रखने का आधार है। मातृभाषा मनुष्य के संस्कारों की संवाहिका है। मातृभाषा के बिना किसी भी देश की संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। यूरोप में हुए एक शोध में यह तथ्य निकलकर सामने आया है कि जो बच्चे स्कूलों में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और घरों में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। वे दूसरे बच्चों की अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिमान और मेधावी होते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बन सका क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की थी। ऐसे में समझ सकते हैं कि मातृभाषा की महिमा अपार है। जिसे सिर्फ शब्दों में बांधना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक भाषा प्रेमी इसे महसूस अवश्य कर सकता है। भला हो केंद्र की मोदी सरकार का जिसने नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की बात कही।

अंततोगत्वा मातृभाषा ही वह आईना है, जिसमें व्यक्ति की संस्कृति और सभ्यता झलकती है। विभिन्न भाषाओं के सांस्कृतिक विविधता और महत्व के बारे में जागरूकता लाना ही अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सर्वोपरि उद्देश्य है। जिसकी पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देने की आवश्यकता है। मातृभाषा को जब हम विशेषकर भारत के परिपेक्ष्य में देखते हैं तो हमारा देश विविध संस्कृति और भाषाओं का देश रहा है। साल 1961 की जनगणना के अनुसार, देश के भीतर अमूमन 1652 भाषाएं बोली जाती थी। जिनकी संख्या वर्तमान में घटकर लगभ 1365 रह गई है। यानी छह दशकों में देश के भीतर ही 287 मातृभाषाएं गायब हो गईं। ऐसे में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा तो हम बनाने की दिशा में सोचें, लेकिन गायब होती मातृभाषाओं का संरक्षण करने की दिशा में भी व्यापक पहल हो, क्योंकि हिंदी माथे की बिंदी तभी है। जब ये क्षेत्रीय बोलियां या मातृभाषाएं हिंदी को सुशोभित करती हैं।

मातृभाषा मनुष्य के विकास की आधारशिला होती है, क्योंकि जब एक बच्चा मां रूपी शब्द का पहली बार उच्चारण करता है। तो वह अपनी मातृभाषा में ही करता है। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है, मां की भाषा। अर्थात वह भाषा जिसे बालक अपनी मां के सान्निध्य में रहकर सीखता है। इसलिए कई बार मातृभाषा को ह्यपालनेह्न या ह्यहिंडोलह्न की भाषा कहते हैं। मातृभाषा को बालक अपने माता-पिता, भाई-बहन या आस-पड़ोस के वातावरण में रहकर सीखता है। इसलिए हर व्यक्ति की कोई ना कोई मातृभाषा अवश्य होती है, बाकी की अन्य भाषाएं व्यक्ति के लिए सम्पर्क भाषा का ही काम करती हैं। एक बालक अपनी मां के सम्पर्क में ही अधिक रहता है, इसलिए बचपन में सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहा जाता है और इस दृष्टिकोण से मां और मातृभाषा में बहुत निकटता का सम्बंध है। जिस तरह व्यक्ति के जीवन में एक मां का अहम योगदान होता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति के जीवन में मातृभाषा भी महत्वपूर्ण होती है। मां बच्चे की जननी होती है, तो मातृभाषा भावों और विचारों के सर्वप्रथम आदान-प्रदान का माध्यम होती है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मातृभाषा की श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए कहा है कि, ह्यमनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही जरूरी है, जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। बालक पहला पाठ अपनी माता से ही पढ़ता है, इसलिए उसके मानसिक विकास के लिए उसके ऊपर मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा लादना मैं मातृभूमि के विरूद्ध पाप समझता हूं ह्न इस कथन से हम और आप समझ सकते हैं कि मातृभाषा किसी भी व्यक्ति और समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत करते हुए प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन भी किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुरूआत 17 नवम्बर 1999 से हुई है और यह यूनेस्को द्वारा घोषित दिवस है। जिसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को उनकी भाषा के प्रति लगाव उत्पन्न कराना है, ताकि विलुप्त होती विभिन्न भाषाओं का संरक्षण किया जा सके।

यूनेस्को के अनुसार दुनियाभर में लगभग 6000 भाषाएं हैं। जिनमें से करीब 2680 भाषाएं अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं यानी कि दुनिया की लगभग 43 फीसद भाषाएं खत्म होने की कगार पर हैं। आज दुनिया भले हथेली पर सिमट गई है, लेकिन यह बदलाव भाषाओं और संस्कृतियों की विलुप्ति का कारण भी बन रहा है। जानकर हैरानी होगी कि एक आंकड़े के मुताबिक हर महीने दुनिया भर से लगभग दो भाषाएं गायब हो रही हैं। अब सोचिए अगर इस तरह भाषाएं गायब होती रही या उन्हें बोलने वाले लोग नहीं बचें ! फिर उन तमाम संस्कृतियों और सभ्यताओं का क्या होगा, जो इन्हीं भाषाओं पर टिकी हुई हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के बड़े मूर्धन्य लेखक और साहित्यकार रहे हैं। जिसके नाम पर हिंदी साहित्य का एक पूरा काल विभाजन किया गया है। उन्होंने आज से लगभग डेढ़ सदी पहले लिखा था कि, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति की मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के शूल। भारतेन्दु ने इस पंक्ति को जब लिखा था, तब शायद ही किसी को भान रहा हो कि एक दिन ऐसा भी आएगा, जब भाषाओं को बचाने के लिए दिवस विशेष की आवश्यकता पड़ेगी ! लेकिन कुछ लोग कालखंड से पहले की सोच रखते हैं और उसी में से एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान और प्रकांड विद्वान हुए हैं।

निःसंदेह किसी मातृभाषा के लुप्त होने का अर्थ उस समाज की संस्कृति और सभ्यता का पतन होना है, जिस भाषा को बोलने वाले लोग नहीं बचें। उस संस्कृति का विनाश निकट है। मातृभाषा में अपना एक अलग ही मर्म और अपनापन होता है। जो किसी दूसरी भाषा में नहीं। मां और ईश्वर इन दोनों शब्दों को ही देखिए। अपनी मातृभाषा चूंकि हिंदी है। इसमें इन दोनों शब्दों के उच्चारण में एक अलग ही अनुभूति होती है। जो मॉम और गॉड में कहां? हिंदी भाषा तो सचमुच में अतुलनीय है। इसमें भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्द हैं। जो किसी दूसरी भाषा में नहीं। ईश्वर को हम हिंदी भाषा में कितने शब्दों से सुशोभित कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हमें केवल गॉड शब्द पर ही निर्भर रहना पड़ता है। भारत में वैसे हिंदी सर्वस्वीकृत भाषा है, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों की मातृभाषा भी अलग-अलग हैं। जो एकता के सूत्र में बंधकर हिंदी का गौरवगान करती हैं।

ऐसे में जिस तरह जन्म के बाद बच्चा मां की गोद में ही पलता और बढ़ता है। वह सबसे ज्यादा अपनी मां के ही सम्पर्क में रहता है। उसी प्रकार जिस भाषा में एक मां अपने बच्चे से बोलती है, बच्चा भी वही सीखता है और यही उसकी मातृभाषा बन जाती है। यदि यह भाषा हिंदी होगी, तो बच्चा भी हिंदी ही बोलने की कोशिश करता है। ऐसे में हम कह सकते है कि मां ही उसकी भाषा को सबसे पहले समझती भी है। मनुष्य का मां से रिश्ता मातृभाषा के साथ ही जुड़ता है। सीधा सा आशय है कि बच्चा जिस वातावरण में पलता और बढ़ता है, वही भाषा उसकी मातृभाषा बन जाती है। मातृभाषा निजी भावों की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त, सरल, सुगम व स्वाभाविक माध्यम है। मातृभाषा अपनत्व, संवेदना, ममता और समता का भाव साथ में लेकर चलती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदी मातृभाषा वाली जगह पर इंग्लिश सीखकर आ जाता है और वह अंग्रेजी को ही सामान्य बोलचाल की भाषा में अपना लेता है तो स्वाभाविक रूप से यह समता और अपनत्व के भाव को कमजोर करेगी। इसलिए व्यक्ति सम्पर्क और जरूरतों के लिहाज से भले ही कितनी ही भाषा क्यों न सीख लें? फिर भी उसे मातृभाषा का मोह नहीं त्यागना चाहिए!

सम्पूर्ण प्रयागराज इन दिनों श्रद्धालुओं से पटा पड़ा रहा । चारों तरफ कई दिन तक भीषड़ जाम की स्थिति बनी रही । गाड़ियों के बीच बीस से तीस घंटे तक लोगों को सड़कों पर फंसे रहना बेहद कष्टदाई रहा । फरवरी माह में माघी पूर्णिमा के कारण प्रयागराज जाने वाले सभी रूट जाम से जूझते रहे । सबसे बुरी स्थिति स्वयं प्रयागराज शहर और भदोही सहित अन्य टोल प्लाजाओं के आस पास की रही है। आखिर इस जाम और फैली अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है ?

कहां भरोगे पाप की कमाई , मौकापरस्तों ने तीर्थयात्रियों से लूट मचाई

सम्पूर्ण प्रयागराज इन दिनों श्रद्धालुओं से पटा पड़ा रहा । चारों तरफ कई दिन तक भीषड़ जाम की स्थिति बनी रही । गाड़ियों के बीच बीस से तीस घंटे तक लोगों को सड़कों पर फंसे रहना बेहद कष्टदाई रहा । फरवरी माह में माघी पूर्णिमा के कारण प्रयागराज जाने वाले सभी रूट जाम से जूझते रहे । सबसे बुरी स्थिति स्वयं प्रयागराज शहर और भदोही सहित अन्य टोल प्लाजाओं के आस पास की रही है। आखिर इस जाम और फैली अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है ? बतौर विश्लेषक यह मेरा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर सरकार को देना है की व्यवस्था में चूक कहा हुई और कथित दावो का सत्यापन वहां की बेतहासा भीड़ और अव्यवस्था कर रही । मैं इस क्राउड ब्लास्ट का स्वयं प्रत्यक्षदर्शी रहा जब विगत 8 फरवरी को महाकुंभ के सेक्टर 19 स्थित ब्रह्मराष्ट्र एकम विश्व महासंघ आश्रम में एक रात्रि गुजारने के बाद मैं यह कॉलम लिखना पड़ा । एक रिपोर्ट में यह दावा भी था की सरकार की तैयारी 50 करोड़ लोगों के आने को लेकर है, लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं चरमराई । सवाल उठना लाजमी हैं। उधर हाइवे पर जाम लगने की वजह से तमाम दुकानदार, ढाबा संचालक, और वाहन चालक मनमानी पर उतर आए। कई के यहां भोजन खत्म हुआ तो कुछ अन्य ढाबे वालों और दुकानदारों ने बिस्किट और भोजन के रेट बढ़ा दिए। एक तरफ आस्था की भीड़ में भूखे प्यासे श्रद्धालु हैं जो कई किलोमीटर पैदल चलकर पुण्य की डुबकी लगाने आ रहे हैं, दूसरी ओर ऐसे पापी लोग भी हैं जो इस अवसर का अनैतिक लाभ उठा रहे हैं। आखिर इस पाप की कमाई को कहा भरेंगे ! हाईवे पर जब कई किलोमीटर लंबा जाम लगा तो मैने स्वयं देखा की ढाबे वाले मुंहमांगा दाम वसूलने लगे। एक अखबार के छपी रिपोर्ट के मुताबिक 400 रुपये में आलू पराठा तो 500 में दाल फ्राई बिकने लगे। उसी अखबार के दावे के मुताबिक निजी वाहन से प्रयागराज पहुंचे 70 वर्षीय विनय किशोर बताते हैं, मैंने अपने जीवन में ऐसा जाम नहीं देखा। फतेहपुर से प्रयागराज के बीच तमाम ढाबों में उन्हें भोजन नहीं मिला। जहां मिला भी तो वहां आलू के एक पराठे के लिए 400 रुपये उन्हें चुकाने पड़े। चाय भी 50 रुपये में एक कप मिली। इसी तरह गंगा स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे मुरादाबाद के प्रशांत वत्स ने लखनऊ रूट के ढाबों के मनमाने रेट पर नाराजगी जताई। कहा कि ढाबे वालों ने जाम का बहुत फायदा उठाया। प्रशांत ने बताया कि चार पूड़ी-सब्जी के लिए उन्होंने 250 रुपये चुकाए जबकि बीस रुपए के एक पैकेट बिस्कुट के लिए उनसे चालीस रुपए मांगे गए । एक तीर्थ यात्री अभिषेक ने बताया कि कानपुर से प्रयागराज के बीच कई ढाबों में तो खाना ही नहीं मिला। फतेहपुर के पास एक ढाबे में भोजन मिला भी तो उसने मुंहमांगा दाम लिया। दाल, सब्जी और दो रोटी के लिए उसने 750 रुपये वसूल लिए। प्रयाग शहर आने वाले सभी हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें बीते तीन दिन से लगी हुई हैं। इसका फायदा तमाम बगैरत लोग उठा रहे हैं जो शर्मनाक है । आगरा के सिकंदरा में रहने वाले अभिषेक ओझा एक प्राइवेट टैक्सी से प्रयागराज पहुंचे लेकिन यहां पहुंचने में उन्हें 26 घंटे का वक्त लग गया। बसंत पंचमी के बाद एकाएक महाकुंभ में बाहरी लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। वाहनों का प्रवेश प्रयागराज में बढ़ गया। प्रशासन यह कहता रहा कि प्रयागराज के स्थानीय वाहनों को छोड़कर अन्य स्थानों की गाड़ियां शहर से बाहर पार्क होंगी, लेकिन धरातल पर स्थितियां बदतर होती चली गईं। आखिर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने पर कैसे उसे नियंत्रित किया जाए? यह सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के सामने होती है। भीड़ के मनोविज्ञान को समझने में कहीं न कहीं प्रशासन से चूक हुई है। जैसे-जैसे प्रयागराज में भीड़ बढ़ी और जाम की स्थिति उत्पन्न होने लगी, श्रद्धालुओं की मजबूरी का फायदा स्थानीय बाइक वाले भी अब उठाने लगे है तीन किमी ले जाने के पांच सौ तक चार्ज कर रहे । और आटो वाले तो चंद किलोमीटर के हजार-हजार या उससे भी अधिक रुपए वसूल रहे हैं। आखिर इस लूट का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन को पता नहीं होगा कि धरातल पर ऐसा चल रहा है। सबसे विकट स्थिति यह है कि ट्रैफिक कंट्रोल में लगे पुलिस वाले असहाय नजर आते हैं। वो केवल लोगों को परेशान होते देख रहे हैं। अधिकांश पुलिसकर्मियों के बाहरी जिलों के होने के कारण वो लोगों का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। धन्य है महाकुंभ जिसने पाप - पुण्य, अमीर - गरीब , लुटेरे - मसीहा और संत समागम के दर्शन एक साथ करा दिया ।

पंकज सीबी मिश्रा
जौनपुर

भगदड़ मानव निर्मित आपदा

भगदड़ भीड़ प्रबंधन की असफलता की स्थिति में पैदा हुई मानव निर्मित आपदा है। भगदड़ प्रायः भीड़ भरे इलाको में किसी अफवाह के कारण भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण भी यह आपदा पैदा होती है। इसमें संपत्ति से अधिक जान की क्षति होने की संभावना रहती है। भीड़ दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के वैश्विक डेटाबेस के मुताबिक सन 2000 के बाद से भारत में 50 से ज्यादा विनाशकारी सामूहिक समारोहों में दो हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इन दुर्घटना को देखते हुए प्रभावी भीड़ प्रबंधन तंत्र विकसित करने की बहुत जरूरत महसूस की जा रही है। खासकर कुंभ जैसे बड़े आयोजनों में इसकी काफी जरूरत महसूस होती है।

भगदड़ बेहद खतरनाक और घातक स्थिति होती है। किसी भी जगह पर जब भीड़ उसकी क्षमता से अधिक हो जाती है और लोगों के पास निकलने का रास्ता नहीं होता है। भीड़ की वजह से लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में किसी तरह की अफवाह या दुर्घटना होने पर भीड़ बेकाबू हो जाती है। इसे भीड़ में हलचल भी कहा जाता है। इसकी वजह से ही भगदड़ की स्थिति बनती है। इसी तरह भीड़ में हलचल का मतलब भीड़ का बेतरतीब तरीके से एक से ज्यादा दिशाओं में एक ही समय में आगे बढ़ना है। ऐसे में लोगों को चलने के लिए जगह कम होती है वो एक-दूसरे के बीच दब जाते हैं। जब लोग एक-दूसरे से बहुत नजदीक होते हैं तो ह्यफोर्सेज का ट्रांसमिशनह्न यानी बल का संचरण हो सकता है। इस फोर्स ट्रांसमिशन को आपने भी कभी न कभी तब महसूस किया होगा जब आप एक बहुत भीड़-भाड़ वाली किसी लाइन में खड़े हुए होंगे। जब पीछे से अचानक धक्का लगता है तो व्यक्ति खुद भी उस धक्के को अपने से आगे खड़े व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में अपना संतुलन बनाए रखना और अपने पैरों पर खड़े रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।

देश में हम आए दिन भीड़ में भगदड़ मचने से कई लोगों के मरने की खबरें पढ़ते रहते हैं। हाल ही में महाकुंभ स्नान के दौरान प्रयागराज में भीड़ में भगदड़ के चलते 37 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वालों की भीड़ में अचानक भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। यह दोनों ही दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व दुखद है।

देश में भगदड़ में मरने वालों की सूची बहुत लंबी है। सभी को पता है कि जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित होगी वहां कभी भी भगदड़ मचने की स्थिति पैदा हो सकती है। मगर अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है जिससे भगदड़ की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होने पाए। सरकारी भी भगदड़ होने के बाद उसको रोकने के ढोल पीट कर कुछ समय बाद शांत बैठ जाती है। मगर ऐसा कोई स्थाई तंत्र विकसित नहीं किया जाता है। जिससे भगदड़ की स्थिति होने से पहले ही सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट मिले और वह उन पर नियंत्रण कर सके।

ये पहली बार नहीं था जब किसी धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मची हो। इसके पहले भी समय-समय पर भगदड़ मचने की खबरें सामने आती रही हैं। इन घटनाओं में कई लोगों की जान भी चली गई। 27 अगस्त 2003 महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुंभ मेले में स्नान के दौरान भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई थी। 25 जनवरी 2005 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंधारदेवी मंदिर में भगदड़ मच गई थी। जिसमें 340 से ज्यादा श्रद्धालु कुचले गए थे। 3 अगस्त 2008 हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में मची भगदड़ में 162 लोगों की मौत हो गई थी। 30 सितंबर 2008 राजस्थान के जोधपुर शहर में चामुंडा देवी मंदिर में मची भगदड़ में लगभग 250 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालु महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ में 63 लोगों की मौत हो गई थी.।

14 जनवरी 2011 को केरल के इडुक्की जिले के पुलमेडु में सबरीमाला मंदिर में एक जीप की टक्कर से मची भगदड़ में 104 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी घाट पर मची भगदड़ में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई थी। 19 नवंबर 2012 को पटना में गंगा नदी पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल के ढह जाने से भगदड़ मच गई थी जिसमें 20 लोगों की मौत हो गयी थी।

13 अक्टूबर 2013 मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि के जश्न के दौरान भगदड़ मचने से 115 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 3 अक्टूबर 2014 को दशहरे का जश्न समाप्त होने के तुरंत बाद पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मच गई जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई थी। 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में पुष्करम उत्सव के पहले दिन गोदावरी नदी के तट पर भगदड़ मचने से 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 1 जनवरी 2022 को जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई थी। 31 मार्च 2023 को इंदौर शहर के एक मंदिर में रामनवमी के मौके पर एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर बनी स्लैब के ढह जाने से 36 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।

इसी तरह रेलवे स्टेशनों पर भी भगदड़ के कारण कई बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। 28 सितंबर 2002 को लखनऊ में बसपा की रैली से वापस घर लौटते समय ट्रेन की छत पर चढ़ने से चार लोगों की करंट लगने से मौत हो गई थी। 13 नवंबर 2004 को नई दिल्ली स्टेशन पर छठ पूजा के दौरान बिहार जाने वाले ट्रेन का प्लेटफार्म अचानक बदलने से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए ओवरब्रिज पर मची भगदड़ में चार यात्रियों की मौत हुई थी। 03 अक्टूबर 2007 को मुगल सराय जंक्शन पर भगदड़ मचने के कारण 14 महिलाओं की मौत हो गई थी। 10 फरवरी 2013 को इलाहाबाद में कुंभ मेला के दौरान रेलवे जंक्शन पर भगदड़ मचने से 38 लोगों की मौत हो गई थी। 29 सितंबर 2017 के दिन मुंबई के एलफिंस्टन रेलवे स्टेशन में बने फुटओवर ब्रिज पर भगदड़ मचने के कारण 22 लोगों की मौत हुई थी।

हमारे देश में आए दिन जगह-जगह बड़े-बड़े धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व अन्य कई प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। जिनमें हजारों-लाखों लोग शामिल होते हैं। ऐसे ही कार्यक्रमों में जरा सी लापरवाही भगदड़ का कारण बन सकती है। ऐसे में यदि कार्यक्रम के आयोजक सावधानी बरतते हुए भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम करें तभी किसी तरह की दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन व प्रयागराज के महाकुंभ में भी जो भगदड़ की स्थिति पैदा हुई है उसमें प्रशासनिक चूक रही है। एक स्थान पर अधिक भीड़ इकट्ठी होने पर यदि प्रशासन के अधिकारी सतर्कता बढ़ाते तो ऐसी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता था। आगे भी सरकार को चाहिए कि ऐसे किसी भी बड़े आयोजनों के लिए और अधिक पुख्ता व्यवस्था करें। देश में आपदा राहत बल को भी अधिक सशक्त किया जाये ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

घूँघट की बगावत

23 फरवरी 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

भारतीय राजनीति में सड़ांध उठने में अधिक समय नहीं लगेगा

भारत के वाम आंदोलन के प्रणेता एम एन राय ने कहा था। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र कार्यपालिका को नियंत्रित नहीं कर सकता। दो चुनावों के बीच की अवधि में संसद में बहुमत वाला दल संवैधानिक रूप से अंधिनायकवादी शक्तियां ग्रहण कर सकता है। लोकतांत्रिक अनुमोदन से संभव शक्ति के इस दुरुपयोग के विरुद्ध कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है। यह सुरक्षा केवल बहुमत दल के नैतिक बोध पर निर्भर करती है। इस प्रकार औपचारिक संसदवाद हर परिस्थिति में लोकतंत्र को बचाने और नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा में सफल नहीं हो सकता। इस संदर्भ में वे केवल हिटलर को ही अपवाद नहीं मानते हैं। आज भारतीय लोकतंत्र भी इसी तरह की दुविधा में झूल रहा है। राज्य हो या केन्द्र चुनावों के बीच का काल कमोवेश राजनीतिक और सामाजिक शून्यता का काल बनता जा रहा है। ऐसा लगने लगा है कि इन वर्षों में भारत की राजनीतिक चेतना गहरी निंद्रा की भेंट चढ़ जाती है। जब भी दो चुनावों के बीच जिस किसी ने भी राजनीतिक सक्रियता कायम रखी है जिसके नतीजे बेहद सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। इसके उदाहरण हैं अस्सी के दशक में जय प्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जिसने सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है और दूसरा हालिया उदाहरण है- राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3500 किलोमीटर की 136 दिवसीय यात्रा और इसके बाद कच्चा न्याय यात्रा का भी राजनीतिक लाभ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला है।

वस्तुतः चुनाव के तुरंत पहले किसी भी बदलाव को लेकर मतदाता बहुत आशान्वित नहीं हो पाता है। उसे लगता है कि इस जंग लगे उपकरण से काम नहीं चलेगा। राजनीति तो सतत प्रवाह मभ प्रक्रिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आजादी के पहले समावेशी-बरित्र का पुनः अध्ययन किया जाये। आज की परिस्थितियों और महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने की परिस्थितियों में बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। उस दौरान में देश में बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, बीमारी, सोप्रदायिकता, जातिवाद किसत्तों और मजदूरोंको बेकद्री आदि कमोवेश चरम पर थी। आज 110 साल बाद फिर हालात बिगड़ रहे है। बेरोजगारी पिछले 50 वर्षों के चरम पर है। आजादी के बाद से देश कभी इतना साम्प्रदायिक यहीं था जितना आज है। किसानो से सालों साल चुनी हुई सरकारें मिलने तक से इनकार कर देती हैं। 40 दिन से अनशन पर बैठे किसान से बात करने का समय एक महीने बद का दिया जाता है। बही आर्थिक असमानता तो औपनिवेशिक काल की सीमा को भो पार कर चुकी है। दिल्ली विधान सभा चुनावों के नतीजों से गाह स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय राजनीति अब गहरे पानी को मानिंद हो गई है और इसमें सड़ांध उठने में अब ज्यादा समय नहीं है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने चुनाव और उसके बाद सत्ता पाने तक को ही राजनीति का हयेय गान लिया है। अतएव हमें कफिन तर्तमान राजनीतिकक सक्रियता पांच वर्षों में महज पांच छः महीने ही बिखाई पड़ती है। बाकी समय आरोप-प्रत्यारोप को मेंट-बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने भारत को एक पूर्णकालिक चुनावी देश में बदल दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के मतदान के ठोक पहले आठवें वित्त आयोग के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संगम स्नान और उसका मीडिया कवरेज और उसके अलावा केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग को आयकर में 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किया जाना, बहुत सीधे, सपाट और स्पष्ट संकेत दे रहा है कि भारत में व्याप्त वर्तमान परिस्थितियों से बहुत से प्रश्न खड़े हो रहे हैं और यह बात भी उभर कर आ रही है कि भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में अस आमूलचूल परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। और उसे लंबे समय तक टाला भी नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी ने सन् 1925 में समझाया था कि- मैं यहां सिद्ध कर। दिखाने की आशा रखता है कि सच्चा स्वराज थोड़े लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त करने से नहीं बल्कि सब लोगों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिकार करने हासिल किया जा सकता है। अन्य शब्दों में- स्वराज जनता में इस बात का शान पैदा करने, प्राप्त किया जा सवाल है कि सत्ता पर नियंत्रण और नियमन करने की क्षमता उसमें है। जबकि आज स्थिति एकदम उलटी नजर आ रही है। जनता के मन में कमोवेश या बैठा दिया गया है कि वह शासन नहीं बल्कि होने के लिए है। इतना ही नहीं उसे यह भी समझा दिया गया है कि उस पर राज्य, शासन, नियंत्रण काबू आदि रखने के लिए सिर्फ एक कठोर ही नहीं कमोवेश निष्ठुर नेता की आवश्यकता है और अमुक नेता उस आवश्यकता की पूर्ति अत्यंत अलोकतांत्रिक होकर लोकतंत्र में संसद या विधान सभाओं के जरिए करता है। कठोरता और निष्ठुरता की आड़ लेकर आज शासन-प्रशासन की सारी असफलताओं को बड़ी सफाई और सफलता से दबाया जा रहा है। यही नहीं गांधी इसे और भी सावट रुख से समझाते हुए कहते हैं कि- सत्ता केवल विधानसभा के जरिए ही हाथ में आती है। यह हमारी जड़ता या मोह का परिणाम है। वास्तविकता यह है कि- सत्ता जनता के हाथों में होती है। और वह कुछ समय के लिए उन लोगों के हाथों में सौंपा जाता है जिन्हें जनता चुनती है। जनता से अलग पार्लियामेंटों की कोई सत्ता या हस्ती नहीं होती है। पार्लियामेंट की पद्धति तभी लाभकारी हो सकती है, जब उसके सदस्य बहुमत की इच्छा के अनुसार चलने को तैयार हों। आज ठीक सौ वर्षों बाद एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां बहुमत नहीं बहुमतवाद का बोलबाला बढ़ रहा है। 35 या 36 प्रतिशत मत लाकर बनी सरकारें प्रायः मनमानी पर उतर आई हैं। अतएव आवश्यकता है बाकी के 65 प्रतिशत को सक्रिय करने की और सत्ता पक्ष से जुड़े समुदाय की आंख में आंख डालकर राजनीतिक गतिविधियों को समाज के सबसे निचले स्तर से पुनः शुरू करने की। गांधी जी ने यही किया था। कुलीनों की कांग्रेस को उन्होंने किसानों और वंचितों की कांग्रेस में परिवर्तित कर दिया था। और पहली बार महिलाओं को अनेक मोर्चों की सीधी जिम्मेदारी सौंपी थी। शराब बंदी एक राष्ट्रीय मिशन बन गया और भारत की अधिकांश जनता इसके माध्यम से जुड़ गई। तब आजादी प्राप्त करना संघर्ष का केंद्रबिंदु था। आज ऐसे तमाम विषय मौजूद हैं। जो लोगों को एकजुट कर सकते हैं। लेकिन राज्यों को द्वारा अपने स्थानीय मुद्दों को जैसे अनावश्यक समझा गया। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले बीस वर्षों में किसी भी दल द्वारा कोई भी ऐसा राजनीतिक आंदोलन सामने नहीं आया जिससे राज्य स्तरीय हलचल हुई हो। राजनीतिक आंदोलन अब विरोध प्रदर्शन तक सीमित हो गए हैं और दलों के राज्याध्यक्ष अधिकांश मामलों में कलेक्टर को साथ सौंप कर अपने राजनीतिक कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं।

भाजपा सरकार के द्वारा जारी नई शिक्षा नीति को लेकर विपक्षी दलों की ओर से शायद ही कभी कोई राष्ट्रीय संगोष्ठी या विमर्श का आयोजन सामने आया हो। ठीक वैसा ही आर्थिक नीति को लेकर भी है।

कारपोरेट एकाधिकार के मुद्दे पर बाकी दलों खास कर कांग्रेस की नीति क्या होगी? किसान और कृषि समस्या का हल तीन कानून के रद्द होने या न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिलवा देने से नहीं निकल सकता। प्रसिद्ध समाजवादी विचारक मधु लिखते हैं- कांग्रेस के अधिवेशन में सन 1920 तक सामाजिक प्रश्नों पर विचार हुआ (कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी) न अके ऊपर किसी तरह का प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया। यह स्थिति गांधी जी के आगमन तक रही। सन 1919 में रौलेट एक्ट विरोधी आंदोलन को लेकर गांधी जी ने भारतीय राजनीति के क्षेत्र पर अपना कदम रखा। उनके असहयोग के अभिनव विचार और कार्यक्रम ने कांग्रेस जनों तथा साधारण लोगों को आकर्षित किया और गांधी जी का नेतृत्व सन 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन तक सुप्रतिष्ठित हो गया। नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया और मुख्य प्रस्ताव में पहली बार कांग्रेस सामाजिक प्रश्नों को अपने आंदोलन का प्रबल हथियार बनाने लगी थी। इन्हीं अधिवेशनों में भविष्य का धर्मनिरपेक्ष भारत गढ़ा गया। वर्तमान समय में राजनीति को एक बड़ी समस्या है। वह यह कि - यह पूरी तरह से सिर्फ कार्यकताओं पर निर्भर हो गई है। और लोक शिक्षण प्रशिक्षण और जनभागीदारी का कार्य पूरी तरह से उपेक्षा हो गया है। मुख्य धारा के मीडिया की बेरुखी भी भारत के भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। परन्तु राजनीतिक दलों को इसका विकल्प तैयार करना होगा। आजादी के पहले भी भारतीय प्रिंट मीडिया का अधिकांश तो का भक्त ही था। अंग्रेज सरकार गांधीजी ने अपने प्रकाशनों और कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के माध्यम से जो वातावरण तैयार किया वह सबके सामने है।

प्रसिद्ध पत्रकार पी. साईं नाथ की पुस्तक - दि लॉस्ट हीरोज : फुट सोल्जर्स ऑफ, इंडियन फ्रीडम' में एक अनूठे पत्रकार कर्नाटक के स्व. एच.एस. दोरेस्वामी पर बेहद रोचक आलेख है। इस का शीर्षक है- वन न्यूज पेपर मेनी नेम्स। दोरेस्वामी ने 104 वर्ष की उम्र पाई थी। वह बताते हैं कि-कलेक्टर ने यह जानकारी नहीं ली कि मैं इतने सारे समाचार पत्रों का पंजीकरण क्यों कर रहा है। मुद्दा यह है कि- जब वह एक शीर्षक (टाइटल) पर बंदिश लगा देते थे तो मैं दूसरा (अखबार) शुरू कर देता था। हो जब उन्होंने पूर्ववाणी पर रोक लगाई तो मैंने पौरावीरा छापना शुरू कर दिया। आज फिर इसी जुनून की आवश्यकता है। वैसे कांग्रेस के पास अभी भी नेशनल हेराल्ड मौजूद है। जरुरी है कि आम जनता में इसे लोक प्रिय बनाने के पहले इसे दल अपने सदस्यों के बीच साझा करे जिससे वह अपने दल के राजनीतिक मन्तव्यों को समझ सके।

भारतीय लोकतंत्र के लिए हालात लगातार प्रतिकूल होते जा रहे हैं। कुछ वर्ष पहले तक भारत के गैर-सरकारी संगठन के साथ ही तमाम प्रबुद्ध लोगों की प्रतिबद्धता सामाजिक राजनीतिक सरोकारों से थी। वर्तमान सरकार ने प्रत्येक प्रबुद्धता के खिलाफ जैसे संग्राम छेड़ दिया है और गैर सरकारी संगठनों की नाक में नकेल डाल दी है। अधिकांश संगठन अब इस नकेल के आदी होते जा रहे हैं। अतएव राजनीतिक दलों को अब परिवर्तन की पूरी लड़ाई अपने अकेले ही लड़नी होगी।

'द आइसमैन' के नाम से मशहूर सोल सिंगर जेरी बटलर का निधन

'द आइसमैन' के नाम से मशहूर मशहूर सोल सिंगर जेरी बटलर का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। बटलर, जिनकी मधुर, भावपूर्ण आवाज ने दशकों तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, का निधन 20 फरवरी, 2025 को शिकागो स्थित उनके घर पर पार्किंसंस रोग से लंबी लड़ाई के बाद हुआ। बटलर का करियर छह दशकों से भी ज्यादा लंबा रहा, जिसमें 55 से ज्यादा हिट गाने शामिल हैं, जिन्होंने फ्रंइ जॉनर पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके सदाबहार क्लासिक गानों में ₹ओनली द स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर, ₹मेक इट ईजी ऑन योरसेल्फ₹, ₹नीड टू बिलॉन्ग₹, ₹ब्रांड न्यू मीर और ₹नेवर गिव यू अप₹ शामिल हैं। उनकी दमदार कहानी और भावनात्मक गहराई ने उन्हें सोल म्यूज़िक की सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक बना दिया।

सफल एकल करियर शुरू करने से पहले, बटलर कर्टिस मेफील्ड के साथ मशहूर फ्रंइ ग्रुप द इंप्रेशन्स के प्रमुख गायक थे। इस समूह ने 1960 के दशक की ध्वनि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने सामाजिक रूप से जागरूक संगीत के लिए जाना जाता था, जो नागरिक अधिकार आंदोलन के साथ गहराई से जुड़ा था। 1991 में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के साथ इंप्रेशन की विरासत

को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई।

बटलर का योगदान संगीत से परे भी था। एक कलाकार के रूप में अपने शानदार करियर के अलावा, उन्होंने एक लोक सेवक के रूप में भी काम किया, 1985 से 2018 तक कुक काउंटी कमिश्नर का पद संभाला। अपने कार्यकाल के दौरान, बटलर ने समुदाय को बेहतर बनाने वाली पहलों पर अथक परिश्रम किया, खासकर स्वास्थ्य और सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के क्षेत्रों में।

उन्होंने निर्माण समिति के उपाध्यक्ष और स्वास्थ्य और अस्पताल समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। शिकागो में जन्मे और पले-बढ़े बटलर का प्रभाव संगीत और राजनीति से परे भी था। अपने शिल्प और समुदाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें अपने गृहनगर में एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। उन्होंने 1959 में अपनी पत्नी एनेट से शादी की, जो उनकी आजीवन साथी बनने से पहले उनके लिए एक बैकग्राउंड डांसर थीं। 2019 में उनका निधन हो गया, जिससे उनके जीवन में एक गहरा शून्य रह गया।

बटलर का निधन सोल म्यूजिक के एक युग का अंत है, लेकिन उनकी विरासत उन अविस्मरणीय गीतों के माध्यम से जीवित है जो उन्होंने दुनिया को उपहार में दिए। उनके करीबी दोस्त मार्टी, जिन्होंने ळटे को खबर की पुष्टि की, ने उन्हें ₹एक अद्भुत व्यक्ति₹ के रूप में वर्णित किया, जिसका प्रभाव कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। जैसा कि दुनिया उनके नुकसान का शोक मनाती है, सोल समुदाय जेरी बटलर के संगीत और समाज पर गहरे प्रभाव को दशार्ता है।

ज्यादातर लड़कियां इस खेल को खेलती थीं

मेरे हसबैंड की बीवी कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का एक शानदार मिश्रण

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर, रकुल प्रीत सिंह और भूमि पेडनेकर अभिनीत, मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित यह फिल्म मजाकिया संवाद और विचित्र स्थितियों से भरी हुई है जो दर्शकों को अंत तक मनोरंजन करती है। अपने हल्के-फुल्के हास्य के साथ, यह मल्टी-स्टारर एक मजेदार सिनेमाई अनुभव देने में सफल है। मेरे हसबैंड की बीवी कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का एक शानदार मिश्रण है। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर, रकुल प्रीत सिंह और भूमि पेडनेकर अभिनीत, मुदस्सर अजीज द्वारा निर्देशित यह फिल्म मजाकिया संवाद और विचित्र स्थितियों से भरी हुई है जो दर्शकों को अंत तक मनोरंजन करती है। अपने हल्के-फुल्के हास्य के साथ, यह मल्टी-स्टारर एक मजेदार सिनेमाई अनुभव देने में सफल है।

कहानी

दिल्ली की पंजाबी फैमिली का मुंडा अंकुर चड्ढा (अर्जुन कपूर) प्रभलीन कौर (भूमि)से शादी कर-के अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है लेकिन यहां भी सब कुछ ठीक नहीं है करीब पांच साल चली शादी के बाद इन दोनों के रिश्तों में अब पहले जैसी बात नहीं यही वजह है अब यह शादी तलाक से जूझती ही नजर आ रही है. अंकुर शादी की कड़क-ड़ाहट भरी यादों से वह चाहकर भी नहीं निकल पा रहा है. अंकुर का दोस्त (हर्ष गुजराल) उसे दिल से इस टेंशन भरे बुरे वक्त से निकलने में उसकी मदद कर रहा है,लेकिन रिजल्ट जीरो ही है । इसी बीच अपने फैमिली बिजनेस के की एक डील के लिए अंकुर को ऋषिकेश जाना पड़ता है। यहां उसकी मुलाकात अपनी कॉलेज फ्रेंड अंतरा खन्ना (रकुलप्रीत) से होती है और फिर दोनों में प्यार हो जाता है. अब इस मजेदार कहानी का क्लाइमेक्स क्या है यह जानने के किए और क्या उनकी शादी हो पाती है या नहीं इसके लिए आपको मेरे हसबैंड की बीवी देखने के लिए सिनेमा का रुख करना होगा। यह फिल्म फुल पैसा वसूल फिल्म है जो आपकी हर कसौटी पर खरा उतरेगी। फिल्म में अर्जुन की भूमिका काफी इंप्रेसिव है बहुत दिनों के बाद उन्होंने अपनी अभिनय की छाप छोड़ी है, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत की नोकझोंक गुदगुदाती है हर्ष गुजराल की एंट्री अच्छी है उन्होंने काफी मेहनत की है जो फिल्में में दिखाई देती हैं।

निर्देशन

खेल खेल में और हैप्पी फिर भाग जाएगी के निर्देशक मुदस्सर अजीज ने एक सरल लेकिन आकर्षक कहानी बनाई है जो मेरे हसबैंड की बीवी के जरिए आधुनिक दर्शकों को पसंद आएगी। फिल्म को अपने किरदारों को स्थापित करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार कहानी शुरू हो जाने के बाद, यह एक मजेदार प्रवाह बनाए रखती है। पटकथा हास्य, जीवंत बातचीत और मनोरंजक वन-लाइनर्स से भरी हुई है, जो एक हल्का और हवादार देखने का अनुभव सुनिश्चित करती है। हालांकि, अर्जुन कपूर की यह फिल्म आपको कार्तिक आर्यन की फिल्म पति पत्नी और वो की याद दिला सकती है। दिलचस्प बात यह है कि 2019 की इस फिल्म का निर्देशन भी अजीज ने किया था और भूमि ने लगभग वही किरदार निभाया था, जो उन्होंने मेरे हसबैंड की बीवी में निभाया था। फिल्म का साउंडट्रैक दिल को छू जाता है, जिसमें मधुर और उत्साहवर्धक ट्रैक हैं जो समग्र अनुभव को बढ़ाते हैं, हालांकि डांस स्टेप अजीब हैं।

अभिनय

मेरे हसबैंड की बीवी के कलाकारों ने अपने अभिनय के मामले में बेहतरीन काम किया है। सिंघम अगेन में दमदार अभिनय के बाद, अर्जुन कपूर अंक-र चड्ढा के रूप में और भी सहज लग रहे हैं। इसके अलावा, अभिनेता ने इस फिल्म में अपनी कॉमिक टाइमिंग से प्रभावित किया है और आपको आश्चर्य होता है कि क्या उन्हें आगामी मल्टी-स्टारर कॉमेडी फिल्मों में लिया जाना चाहिए था। दूसरी ओर, भूमि पेडनेकर ने एक बार फिर प्रबलिन कौर का किरदार निभाते हुए अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया है। हालांकि, उन्हें स्क्रीन पर देखना और पत्नी पत्नी और वो की वेदिका त्रिपाठी की याद न दिलाना मुश्किल है, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा ही अनुभव हुआ है। दूसरी ओर, रकुल प्रीत सिंह अंतरा की भूमिका में आकर्षण और जीवंतता लाती हैं। वह अर्जुन कपूर के साथ भी अच्छी केमिस्ट्री साझा करती हैं। हर्ष गुजराल, डिनो मोरिया और आदित्य सील सहित सहायक कलाकारों ने फिल्म में अपने समयबद्ध प्रदर्शन से हास्य को और बढ़ा दिया है। हालांकि, शक्ति कपूर मेरे लिए सबसे अलग हैं। एनिमल के बाद उन्हें इस तरह की भूमिका में देखना ताजा करने वाला है।

पूजा एंटरटेनमेंट के तहत वाशु भगनानी, जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख द्वारा निर्मित, मेरे हसबैंड की बीवी हाल ही में रिलीज हुई एक्शन से भरपूर फिल्मों से एक ताजा ब्रेक के रूप में काम करती है। रोमांटिक कॉमेडी और हल्के-फुल्के मनोरंजन के प्रशंसकों को यह फिल्म पसंद आएगी, खासकर वे जिन्हें 2 स्टेट्स, की एंड का और मुबारकां में अर्जुन कपूर पसंद आए थे। जो लोग पीरियड ड्रामा और एक्शन रिलीज के बीच एक सॉफ्ट रोमांटिक कॉमेडी का आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें यह फिल्म खूब पसंद आएगी। हालांकि कहानी में वही सब कुछ है जो पहले से ही चल रहा है, लेकिन फिल्म का हास्य, आकर्षक अभिनय और मनोरंजक क्षण इसे कॉमेडी प्रेमियों के लिए एक आनंददायक फिल्म बनाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को समर्पित एक गीत 'ये शंखनाद है' जारी

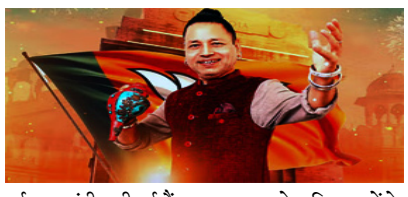

मशहूर गायक कैलाश खेर ने गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को समर्पित एक गीत 'ये शंखनाद है' जारी किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी राजधानी में अपनी सरकार बना रही है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। वह गुरुवार को 6 विधायकों के साथ रामलीला मैदान में शपथ लेंगी। इस बीच पद्मश्री से सम्मानित गायक कैलाश खेर ने दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए एक संगीतमय तोहफा दिया। उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए एक विजय गीत तैयार किया है। खेर के इस गीत का शीर्षक 'ये शंखनाद है' है और इसके बोल हैं, 'जय का विजय का, सनातन उदय का, ये शंखबाद है।'

दिग्गज तेलुगु अभिनेत्री चित्तजल्लु कृष्णवेनी का निधन हुआ

तेलुगु सिनेमा के स्वर्ण युग की एक मुख्य हस्ती, तेलुगु अभिनेत्री चित्तजल्लु कृष्णवेनी का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अभिनेत्री ने रविवार, 16 फरवरी को अपने आवास पर अंतिम सांस ली। कृष्णावेनी को कई प्रदर्शन और तेलुगु सिनेमा के प्रति समर्पण के लिए उच्च सम्मान मिला।

कृष्णावेनी का फिल्मी करियर

कृष्णावेनी ने फिल्म उद्योग में अपनी यात्रा सती अनसूया - ध्रुवविजयम (1936) में एक बाल कलाकार के रूप में शुरू की, जहां एक्ट्रेस ने अनसूया का किरदार निभाया। समय के साथ, वह एक मुख्य अभिनेत्री और सिंगर बन गईं। साक्षी पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, कृष्णावेनी ने बाद में मिर्जापुरम के एक जमींदार से शादी की, जो एक फिल्म निमार्ता और शोभनचला स्टूडियो के प्रमुख भी थे। समय के साथ, उन्होंने स्टूडियो के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली और फिल्म निर्माण में उतर गईं। उनका शानदार करियर आठ दशकों तक फैला रहा, इस दौरान उन्होंने सती अनसूया, दक्ष यज्ञ, भोज-कालिदास, जीवनज्योति, तुकाराम, काचा देवयानी और मनदेसम जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया।

एक्ट्रेस ने कई इतिहास रचे

कृष्णावेणी ने जो अच्युतानंद जोजो मुकुंद को अपनी आवाज देकर इतिहास रच दिया, जो तेलुगु सिल्वर स्क्रीन पर अन्नमय्या कीर्तन की पहली प्रस्तुति थी। भारत की आजादी से पहले भी, उन्होंने गोलाभामा में भूपति चम्पिथिन का प्रदर्शन करके अपनी कलात्मक कौशल का प्रदर्शन किया।

एक निर्माता के रूप में, कृष्णवेनी ने मनदेसम (1949) में प्रसिद्ध अभिनेता एन. टी. रामाराव को पेश करके तेलुगु सिनेमा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस फिल्म ने संगीत निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध संगीतकार घंटासाला की शुरूआत भी की। इसके अलावा, उन्होंने संगीत निर्देशक रमेश नायडू और गायिका पी. लीला जैसी प्रतिभाओं को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका प्रभाव अगली पीढ़ी तक भी बढ़ा, जिससे उनकी बेटी एन.आर. अनुराधा को फिल्म निर्माण में मार्गदर्शन मिला।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com